सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 289, नई दिल्ली । शनिवार, 28 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति
06 डिब्बाबंद भोजन से सेहत को खतरा
08 चोर से बरामद 25 लाख का सोना बेंचने में पूर्व थानाध्यक्ष समेत चार दोषी

दिल्ली-एनसीआर से हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां; जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

दिल्ली वालों को एक और राहत मिली है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता सुधरी है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप तीन के प्रतिबंधों को हटा दिया है। हालांकि प्रदूषण स्तर को प्रबंधित करने के लिए चरण 1 और 2 के तहत उपाय लागू रहेंगे। बता दें इससे पहले ग्रेप-4 चार हटाई गई थी।

संजय बाटला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली-NCR वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से हवा की गुणवत्ता सही बनी हुई है।

इसी के चलते CAQM ने आज यानी शक्रवार को पूरे एनसीआर से ग्रेप-3 की पाबंदियां को हटा दिया है। बता दें इससे पहले GRAP-4 की पाबंदियां हटाई गई थी।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दी हैं।

अब दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा, स्कूल खुलेंगे और बीएस 4 डीजल और बीएस 3 पेट्रोल वाहनों पर से प्रतिबंध हट जाएगा। हालांकि, GRAP-2 के तहत कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी।

ग्रेप तीन और चार के तहत हटीं ये पाबंदियां

दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा।

एनसीआर में सभी स्कूल खोले जा सकेंगे।

बीएस चार डीजल और बीएस तीन पेट्रोल के वाहनों पर से प्रतिबंध हटा

निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, लेकिन सख्ती से अपनाने होंगे धूल शमन के उपाय

GRAP दो के तहत ये पाबंदियां अभी भी रहेंगी जारी

आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक

पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश

इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई

सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

फ्री बस सेवा ने महिलाओं को बनाया सशक्त, कमर्शियल वाहन चालकों को भी मिली राहत

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं कि बीते पांच साल में 150 करोड़ पिंक टिकट बिके. इसका मतलब है दस रुपये के हिसाब से सरकार को 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी है. यह सब्सिडी महिलाओं के घर में सीधे बचत के तौर पर पहुंची है.

नई दिल्ली। दिल्ली में आप सरकार की फ्री बस सेवा से महिलाओं के लिए जीवन आसान हुआ है. अब उन्हें काम पर जाने, खरीदारी करने, घूमने या रिश्तेदारों से मिलने जाने पर यात्रा खर्च नहीं उठाना पड़ता. महिलाओं का मानना है कि फ्री बस सेवा से उनके पैसे बच जाते हैं. पिंक टिकट ने न केवल महिलाओं को सहूलियत मिली है बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑनर्स के हालात भी बदले हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट शुल्क से आजाद हुआ है.

एक महिला साल में कितना बचा सकती है

अगर महिलाएं फ्री बस सेवा का इस्तेमाल करती हैं तो ऑटो, टैक्सी, मेट्रो से सफर पर होने वाला खर्च अब उनकी वास्तविक बचत बन गई है. एक अनुमान के मुताबिक फ्री बस से सालाना 1.24 लाख रुपये तक बच सकते हैं. कैसे, इसके लिए हम एक नर्स गुरमीत कौर का उदहारण लेते हैं. वह पहले ऑटो से आना-जाना करती थी, अब फ्री बस से जाती हैं. बस में सफर से अब उनका एक दिन में करीब 400 रुपये बच जाता है. अगर 26 दिन वह काम करती हैं तो आने जाने पर उनका 10,400 और सालाना 1,24,800 रुपये अब उनका बच जाएगा. एक अन्य महिला लाजवंती क्लर्क हैं. वह पहले मेट्रो से ड्यूटी आती-जाती थीं. उनके मुताबिक एक दिन में आने-जाने में उनकी 120 रुपये तक खर्च हो जाते थे. अगर चार दिन की छुट्टी मान लें तो बाकी के 26 दिनों में सफर पर वह 3,120 रुपये खर्च करती थीं. इस तरह अगर साल का जोड़ें तो बस में सफर से उनके 37,442 रुपये बच रहे हैं.लाजवंती इस बचत का जिक्र कर काफी खुश नजर आती हैं.

आर्किटेक्ट मानवी कभी मेट्रो, कभी ऑटो से आना-जाना करती रही थीं. लेकिन अब फ्री बस सेवा का इस्तेमाल कर करीब 96,000 रुपये बचा पा रही हैं. मानवी के लिए भी यह बचत मायने रखती है. यह बचत हर वर्ग के लिए अलग-अलग हैं. फ्री बस ने हर महिला का पर्स बचाया है. हर घर पर इसका सकारात्मक असर हुआ है.

साल में 1500 करोड़ के बिके पिंक टिकट

दिल्ली सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि बीते पांच साल में 150 करोड़ पिंक टिकट बिके हैं. इसका मतलब है दस रुपये पिंक टिकट के हिसाब से दिल्ली सरकार को 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी है. यह सब्सिडी महिलाओं के घर में सीधे बचत के तौर पर निश्चित रूप से पहुंची है. ग्रीन पीस के सर्वे के मुताबिक 75 फीसदी महिलाएं मानती हैं कि परिवहन पर उनका मासिक खर्च कम हुआ है, जो बचत हुई हैं उसका इस्तेमाल 55 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू खर्च में किया है. आधी महिलाओं ने इमरजेंसी फंड में इस बचत को रखा है. जाहिर है जो कॉमन महिलाएं हैं. उन्होंने इमरजेंसी और घरेलू खर्च को मर्ज कर रखा होगा.

दिल्ली में फ्री बस के कारण महिलाओं को बचत के साथ-साथ असुरक्षा की स्थिति से बचाव भी हुआ है, लेकिन अब भी बस से अपने घर तक पहुंचने के लिए उतरने के बाद काफी दूर तक महिलाओं को पैदल चलना पड़ता है. यह यात्रा ऑड आवर्स में असुरक्षित हो जाती है. इस स्थिति में महिलाओं का बचाव करने के लिए मोहल्ला बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है. 140 मोहल्ला बसें सड़क पर उतर चुकी हैं. एक बस में 36 यात्री सफर कर सकते हैं. एक बार में बसें 5040 यात्रियों को सफर करा सकती हैं. आने-जाने के एक ट्रिप पर यह क्षमता 10,080 यात्रियों को सफर कराने की है. सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे में अगर 10 ट्रिप भी बसें चलीं तो 10,08,00 यात्री रोजाना सफर करेंगे।

मोहल्ला बसें भी लाएंगी जीवन में बदलाव

दिल्ली में फ्री बस के कारण महिलाओं को बचत के साथ-साथ असुरक्षा की स्थिति से बचाव भी हुआ है, लेकिन अब भी बस से अपने घर तक पहुंचने के लिए उतरने के बाद काफी दूर तक महिलाओं को पैदल चलना पड़ता है. यह यात्रा ऑड आवर्स में असुरक्षित हो जाती है. इस स्थिति में महिलाओं का बचाव करने के लिए मोहल्ला बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है. 140 मोहल्ला बसें सड़क पर उतर चुकी हैं. एक बस में 36 यात्री सफर कर सकते हैं. एक बार में बसें 5040 यात्रियों को सफर करा सकती हैं. आने-जाने के एक ट्रिप पर यह क्षमता 10,080 यात्रियों को सफर कराने की है. सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे में अगर 10 ट्रिप भी बसें चलीं तो 10,08,00 यात्री रोजाना सफर करेंगे.

हर वाहन चालकों की पांच साल में 30 हजार की बचत

दिल्ली में 2.5 लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं. इनमें करीब एक लाख ऑटो हैं. इन वाहनों के लिए पहले लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए सालाना शुल्क 1416 रुपये देना पड़ता था, जिसे माफ कर दिया गया है. ऑटो और टैक्सियों का ट्रैकिंग शुल्क 2019 में ही माफ कर दिया गया था. 2019 में ही ऑटो चालकों के लिए 200 रुपये का फिटनेस शुल्क खत्म कर दिया गया था. लेट फीस को घटाकर 20 रुपये करते हुए 30 रुपये की बचत कराई गई थी. रजिस्ट्रेशन फीस हजार रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिया गया. डुप्लीटकेट आरसी में आरसी की फीस 500 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दी गई. हायर पर्चेज एडिशन शुल्क 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिए गए. फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 2500 रुपये का शुल्क भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया. ये फायदे 5500 रुपये से ज्यादा के हैं. बीते पांच साल में हुई बचत को जोड़े तो ये रकम 27500 रुपये हो जाती है. इस तरह दिल्ली सरकार की परिवहन नीति ने आम लोगों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की बड़ी बचत कराई है। इससे उनकी जिंदगी में सुधार आया है.

गाजियाबाद में पुलिस का बड़ा अभियान: 413 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 1821 वाहनों की हुई जांच

इशिकामुख्य रिपोर्टर

गाजियाबाद। शहर में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने 26 स्थानों पर एक साथ चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें पहले ही दिन 1821 वाहनों की जांच की गई और 413 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

अभियान का उद्देश्य

गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, इस विशेष अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह अभियान शहर में बढ़ते अपराध और यातायात उल्लंघन की शिकायतों को देखते हुए चलाया गया है।

मुख्य कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि इस चेकिंग अभियान के दौरान बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट और वाहनों के दस्तावेजों के अभाव में कार्रवाई की गई। इसके अलावा, पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले और सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए।

कानून तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी राहत

पुलिस के इस अभियान में हाईवे और मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने 26 स्थानों पर बैरिकेडिंग की और जांच प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया। कई वाहन चालक जिन्होंने दस्तावेज़ नहीं दिखाए, उनके वाहन जब्त कर लिए गए।

स्थानीय लोगों का समर्थन

इस अभियान को लेकर स्थानीय नागरिकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ ने इसे परेशानी भरा करार दिया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और जांच में सहयोग करें।

पुलिस का बयान

गाजियाबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक किया जाएगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि अपराधियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी।

गाजियाबाद पुलिस का यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ भेदभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उबर इंडिया और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया

इशिका मुख्य रिपोर्टर

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उबर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका एक दृष्टिबाधित अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें उबर इंडिया के ड्राइवरों द्वारा उनके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार और MoRTH द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों (PwDs) से संबंधित नीतियों के उचित कार्यान्वयन की कमी का आरोप लगाया गया है।

याचिका के मुख्य बिंदु:

- भेदभावपूर्ण व्यवहार: याचिकाकर्ता ने उबर के माध्यम से एक सवारी बुक की, जिसमें ड्राइवर ने उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया। ड्राइवर ने कैफे के दरवाजे तक उन्हें मार्गदर्शन करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह उसके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कुछ समझाने के बाद ही ड्राइवर ने यात्रा शुरू की, लेकिन फिर भी असम्मानजनक व्यवहार जारी रखा।

- उबर की नीतियों का अनुपालन न करना: याचिकाकर्ता का दावा है कि उबर की शून्य-भेदभाव नीति होने के बावजूद, कंपनी ने अपने ड्राइवरों को दिव्यांगता संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षण देने में विफलता दिखाई है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) की धारा 41 का उल्लंघन है।

- MoRTH की भूमिका: याचिकाकर्ता का आरोप है कि MoRTH ने उबर को RPwD अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने में अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ परिवहन सेवाओं का अभाव है।

याचिकाकर्ता की मांगें:

- उबर से मानसिक पीड़ा, तनाव और असुविधा के लिए ₹1 लाख का मुआवजा।

- RPwD अधिनियम की धारा 89 के तहत उबर पर जुर्माना, क्योंकि उनकी ऐप सुलभ नहीं है और यह वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है।

- MoRTH को निर्देश कि सभी राइड-हेलिंग सेवा प्रदाताओं के लिए सुलभ सेवा मानकों को अपनाने के लिए एक व्यापक कानूनी निर्देश जारी करें, जिसमें सुलभ वाहन, ड्राइवर प्रशिक्षण, ऐप की सुलभता और उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र शामिल हों।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उबर और MoRTH को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च, 2025 को निर्धारित की है।

यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ परिवहन सेवाओं की आवश्यकता और सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके अधिकारों के सम्मान की महत्वपूर्णता को रेखांकित करता है।

सेहत और रिश्ते दोनों बिगाड़ सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन तरीकों से करें इसे मैनेज

अच्छा जीवन जीने के इच्छा हर किसी की होता है लेकिन अपनी इस चाहत को पूरा करने की होड़ में अक्सर लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से न सिर्प मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि कई बार आपके रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे इस स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ तरीके।

नई दिल्ली। इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने और खूब सारे पैसे कमाने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। अपनी और घर-परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही व्यक्ति इन पैसों से सांसारिक खुशियां हासिल करने की कोशिश करता है। हालांकि, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा ज्यादा की मांग करता है और अपनी इसी ज्यादा की इच्छा को पूरा करने के लिए लोग आजकल दिखावे और आडंबर की दुनिया में फंसते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा मिलने लगी है।

अक्सर ज्यादा पैसा कमाने की चाहत या ज्यादा पैसा खर्च करने से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगता है। इसकी वजह से फाइनेशियल स्ट्रेस हो सकता है, जिससे एंग्जाइटी, इन्सोम्निया, हाई बीपी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती हैं। ऐसे में आज हम कुछ तरीके बताने वाले हैं, जिससे आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं।

अपने खर्चे को चेक करें

पैसे मैनेज कर के रखने के लिए आपके पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। फूड, ट्रांसपोर्ट, बिल आदि पर फोकस कर के आप ये चेक करें कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा कहां जा रहा है। बेहिसाब खर्चे आर्थिक स्ट्रेस का कारण बनते हैं, इसलिए अपने खर्चों का हिसाब डायरी में नोट करें।

छोटे मूव, बड़े इंपैक्ट

अपने रिटायरमेंट के लिए छोटे-छोटे ऐसे मूव्स लें, जिससे भविष्य में उसके बड़े इंपैक्ट हों। छोटा अमाउंट ही सही लेकिन रिटायरमेंट के नाम पर एक अमाउंट जमा करते चलें। ये आपके लिए इमरजेंसी फंड का भी काम करता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखता है।

रिश्ते पर हावी न होने दें

अपने निजी रिश्ते में पैसे को हावी न होने दें। इसके लिए आपस में सीक्रेट न रखें, खर्चे न छुपाएं, खुल कर बातचीत करें, अपने आर्थिक लक्ष्यों की चर्चा करें और अपनी आर्थिक गलतियों और निर्णयों पर समय नष्ट करने की जगह भविष्य में कैसे-क्या करना है, उस बात पर विचार विमर्श करें। इससे आर्थिक स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है।

लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च न करें

आजकल सबसे बड़ी गलती हमसे यही होती है कि हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करते हैं। महंगी गाड़ियों और कपड़ों पर खर्च करने की जगह सेविंग, सही जगह इन्वेस्टमेंट और संतुष्टि भरे जीवन पर फोकस करें, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप बिना वजह आर्थिक स्ट्रेस से भी बच जाएंगे।

एडिक्शन से बचें

इंसान डिप्रेशन में आ कर शराब या नशे का सेवन करने में लिप्त हो जाता है। ये अनावश्यक खर्चे होते हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही नुकसानदायक हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी लत से बचें जिसमें पैसे खर्च होने के साथ कोई इजाफा भी नहीं है।

सर्दियों में हेयर ऑइलिंग के हैं कई फायदे, हेयर फॉल के साथ दोमुंहे बालों से मिलेगा छुटकारा

सर्दियों में सेहत के साथ-साथ बालों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इस मौसम में अक्सर सर्द हवाएं बालों को रूखा और बेजान बना देती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस दौरान अपने बालों का खास ख्याल रखा जाए। इस मौसम में बालों में तेल लगाना बेहद फायदेमंद होता है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं।

नई दिल्ली। सर्दियों में हमारी सेहत काफी प्रभावित होती है। सर्व हवाएं और कम होता तापमान कई तरह से लोगों पर असर डालता है। यही वजह है कि इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा सर्दियों में त्वचा और बालों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। सर्द हवाएं अक्सर बालों को रूख और बेजान बना देती है, जिससे बाल रफ और ड्राई नजर आते हैं। इसलिए बालों में तेल लगाना बेहद जरूरी है, खासकर सर्दियों में।

सर्दियों में बालों में तेल लगाने से आपके बालों को जरूरी मॉइश्चर मिलता है। अगर आप उन्हें हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, तो आपके बाल ड्राई और रफ हो जाएंगे। नमी बढ़ाने के अलावा, तेल आपके बालों में चमक भी ला सकता है और आपके बालों के पूरे स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। आइए आपके बताते हैं सर्दी में बालों में तेल लगाने के फायदे-

ड्राइनेस रोके और स्कैल्प हाइड्रेट करे

ठंडे तापमान के कारण सर्दियों में अक्सर स्कैल्प का नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिसकी वजह से स्कैल्प ड्राई हो जाता है। ऐसे में बालों में तेल लगाने से स्कैल्प की नमी बनी रहती है और स्कैल्प पर होने वाली पपड़ी और खुजली से राहत मिलती है।

ब्लड सर्कुलेशन सुधारे

बालों में तेल लगाते समय सिर की मालिश करने से माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों के फॉसिकल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे बालों को ग्रोथ बेहतर होती है और बाल मजबूत और घने बनते हैं।

बालों के फॉसिकल्स को पोषण मिलता है

हेयर ऑयल में फैटी एसिड, विटामिन ई, डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व जब बालों की जड़ों में जाते हैं और फॉसिकल्स को मजबूत करते हैं। साथ ही इससे बालों का टूटना कम होता है और दोमुंहे बालों भी कम होते हैं।

बालों को पर्यावरणीय डैमेज से बचाए

सर्द हवाएं और नमी कम होने से बालों का केराटिन स्ट्रचर टूट जाता है। ऐसे में तेल एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, जो बालों के क्यूटिकल्स को पर्यावरण के कारण होने वाले डैमेज से बचाते हैं और साथ ही प्रोटीन लॉस को भी कम करते हैं।

स्कैल्प इन्फेक्शन को रोके

सर्दी के कारण होने वाली ड्राईनेस के साथ स्कैल्प की खराब देखभाल से माइक्रोबियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। जुलाई 2024 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित स्टडी के अनुसार, बालों में तेल लगाने से फंगस और बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है, जिससे स्कैल्प इन्फेक्शन का खतरा कम होता है।

बालों की चमक बढ़ाए

नियमित रूप से बालों में तेल लगाने से बालों के क्यूटिकल्स मुलायम हो जाते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है और इनमें चमक आती है। ज्यादा बेहतर नतीजों के लिए, लगाने से पहले तेल को थोड़ा गर्म करें और इसे धोने के लिए सल्फेट फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें।

अपने जिगर के टुकड़े को नहलाते हुए न करें ये गलतियां, हो सकती है बड़ी अनहोनी

बच्चे को नहाते हुए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन कई लोग बच्चे को बाथरूम में ले जाकर नहाने को ही नहाना समझते हैं। बता दें कि बच्चे को नहाना एक बड़ी कला है। इसमें बच्चे को आपने बहुत केयर से हैंडल करना होता है। आपकी एक लापरवाही बच्चे को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन गलतियों से बचना चाहिए।

नई दिल्ली। छोटे बच्चे को नहलाना एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों को नहाते समय अगर आप कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते हैं तो यह आपके बच्चे की जान को खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप इन गलतियों को करने सें बचें। यहां कुछ गलतियां हैं जो नहलाते समय करने से बचना चाहिए।

बच्चे को अकेला नहीं छोड़नाः नहलाते समय बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा अचानक पानी में डूब सकता है या फिसलकर गिर सकता है। कोशिश करें कि बच्चे को तभी बाथरूम लेकर जाएं जब आप उसे नहाएं। कई बार बच्चों की मां उन्हें पानी के टब में बैठाकर दूसरे काम में व्यस्त हो जाती हैं। ऐसे में बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है।

पानी का तापमान सही नहीं होनाः पानी का तापमान बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार बच्चे के सिर पर ठंडा पानी डालना और खतरनाक हो सकता है। ऐसे में यह गलती न करें।

बच्चे को साबुन या शैम्पू के संपर्क में नहीं लानाः बच्चे की आंखों और नाक में साबुन या शैम्पू के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इससे बच्चे को दर्द और परेशानी हो सकती है। कोशिश करें कि इस तरह की गलती नहीं करें। शैंपू या साबुन कई बार आंखों में जलन कर सकते हैं। बच्चों की सहनशक्ति काफी कम होती है। इसलिए इससे बचना चाहिए।

सही पोजीशन में नहीं रखनाः बच्चे को नहलाने के लिए सही पोजीशन में रखना महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे को सुरक्षित और आरामदायक महसूस होता है। इसलिए बच्चे को पालथी मारकर बैठाए। बच्चे के नहाने के दौरान उसे सही पोजीशन में बैठाना बहुत जरुरी है। क्योंकि कई बार बच्चे को गलत पोजीशन पर बैठाने से उसका पैर भी सुन हो जाता है।

नहलाने के बाद तुरंत नहीं सुखानाः बच्चे को नहलाने के बाद तुरंत सुखाना महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे की त्वचा को नुकसान पहुँच सकता है और उसे ठंड लग सकती है। कोशिश करें कि नहाने के तुरंत बाद आप बच्चे के बदन का पानी पोछ दें। खासकर सर्दियों के मौसम में बच्चों को नहाने के बाद उन्हें सूखे कपड़े से सूखा दें।

नाश्ते में बनाना है कुछ टेस्टी और हेल्दी, तो इस रेसिपी से ट्राई करें मुरमुरे अप्पे

साउथ इंडियन डिशेज अपने यूनिक फ्लेवर के कारण दुनियाभर में मशहूर हैं। करी पत्ता और राई की महक खाने को एक अलग स्वाद देती है जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इडली की ही तरह बनने वाले अप्पे एक प्रकार की मिनी इडली जैसे लगते हैं लेकिन इसमें मिली सब्जियां और सूजी इसे इडली से अलग बनाते हैं।

अप्पे एक साउथ इंडियन पारंपरिक डिश है, जिसे बनाना बेहद आसान और ये खाने में भी इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सभी बड़े चाव से इसे खाते हैं। इसके साथ ये पौष्टिक भी होते हैं, क्योंकि इसमें तेल मसाले का उपयोग न के बराबर होता है। इन सबके ऊपर इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की संख्या इतनी कम होती है कि ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ता है। अप्पे को बनाने में बहुत कम समय और मेहनत लगती है और अगर स्वाद थोड़ा बदलना हो तो इसमें मुरमुरे पीस कर एक डिफरेंट टेस्ट में तैयार कर सकते है। इसे बनाना जितना आसान है, यह उतने ही पौष्टिक भी ये होते हैं।

कुल मिलाकर इतने सारे फायदों के साथ अप्पे एक जबरदस्त स्नैक्स और नाश्ते का विकल्प बन जाता है, लेकिन आमतौर पर घरों में सूजी के अप्पे बनाए जाते हैं। ये मुलायम, स्पंजी और स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप इसमें ट्विस्ट देना है, तो इस बार ट्राई कर सकते हैं मुरमुरे अप्पे।

मुरमुरे अप्पे बनाने के लिए ये रेसिपी आप तुरंत नोट करें और इसे बना कर आज ही ट्राई करें। आइए जानते हैं मुरमुरे अप्पे बनाने की विधि-

सामग्री

मुरमुरे (1 कप)
सूजी (1 कप)
दही (2 टेबलस्पून)
चिली फ्लैक्स या लाल मिर्च पाउडर
काली मिर्च पाउडर
चाट मसाला
नमक
कद्दूकस किया गाजर
बारीक कटे प्याज
शिमला मिर्च
हरी मिर्च
हरी धनिया
ईनो या सोडा
तड़का के लिए राई
कढ़ी पत्ता
खड़ी लाल मिर्च
सरसों तेल

बनाने का तरीका

सबसे पहले मुरमुरे को पानी में भिगो लें और सूजी में दही और पानी मिलाकर फेंट लें।

मुरमुरे को दस मिनट पानी में भीगने के बाद सूजी के मिक्स के साथ मिक्सर में डाल कर पीस लें।

अब इस मिक्स को कटोरे में निकालें और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लैक्स और काली मिर्च पाउडर डालें।

फिर बारीक कटी हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर को भी इसी में मिलाएं।

अब कढ़ी पत्ता के कुछ टुकड़े भी काट कर डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। बस अप्पे मिक्स तैयार है।

इसके बाद अप्पे पैन के सभी मोल्ड में आधा चम्मच से भी कम तेल डालें।

इसे गैस पर चढ़ा दें और गर्म तेल में जीरा और राई डालें।

इसके ऊपर चम्मच से तैयार अप्पे मिक्स डालें और दोनों तरफ पलट कर सुनहरा होने तक सेंकें।

कढ़ाई में सरसों तेल डाल कर करी पत्ता और राई का तड़का दें। इसमें मुरमुरे अप्पे डाल कर हल्का क्रिस्प होने तक भुनें।

तैयार है टेस्टी और हेल्दी अप्पे। इसे नारियल चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।

अगर डेली लाइफ से निकाल दें पार्टनर से करने वाली ये शिकायतें, रिश्ते में कभी नहीं होगी अनबन

शादी के बाद पति पत्नी के बीच लड़ाई या बहस होना नई बात नहीं है। लेकिन यह तब ज्यादा खतरनाक है जब रोजाना लड़ाई होने लगे। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रोजाना कुछ बातों को अपने जहन में रखें कि आप अपने दांपत्य जीवन में खुश रहें। छोटी-छोटी शिकायतें कई बार बड़ा फर्क डाल देती हैं।

शादी के बाद छोटी-छोटी बातों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह कई बार रिश्ते को कमजोर करने की वजह बन जाती हैं। इसलिए शादी के बाद हर बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है।

अगर ऐसा ना किया जाए तो पता नहीं चलता कि आपके पार्टनर को आपकी किस बात का बुरा लगा और वह आखिर किस बात से आपसे खफा है। इसलिए कई बार मजाक में या संजीदा होकर भी अपने पार्टनर से वो बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे उसके मूड पर असर पड़े।

से जुड़ी आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने जा रहे हैं। रोज की जिंदगी में पार्टनर से शिकायतें करना आम बात है, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो रिश्ते को खराब कर सकती हैं। यहां कुछ शिकायतें हैं जिन्हें रोज की जिंदगी से निकाल देना चाहिए।

छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करना

छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करने से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए, छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करना चाहिए। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है वो उन बातों की भी शिकायत कर देते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। उनकी यह आदत एक दिन उनको अकेला कर देती है।

पार्टनर की आलोचना करना

पार्टनर की आलोचना करने से रिश्ते में नकारात्मकता पैदा हो सकती है। इसलिए, पार्टनर की आलोचना करने के बजाय, उनकी तारीफ करना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर की आलोचना करते हैं तो इसका उनके दिमाग और दिल पर गलत असर पड़ता है। कई बार आपकी यह आदत आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है।

पार्टनर को समय न देना

पार्टनर के पास समय न देने से रिश्ते में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए, पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ बातचीत करना चाहिए। ऑफिस या कारोबार में कई लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह यह भी भूल जाते हैं कि उनके साथ घर में कोई और शख्स भी रहता है।

पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा करना

पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा करने से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए, पार्टनर की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पार्टनर से अपेक्षाएं करने से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए, पार्टनर से अपेक्षाएं करने के बजाय, उनके साथ संवाद करना चाहिए और उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। इन शिकायतों को रोज की जिंदगी से निकाल देने से रिश्ते में सुधार हो सकता है और दोनों पार्टनर खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

सर्दियों में सुबह उठते ही कर लीजिए बस ये 4 योगासन, तेजी से घटेगा यूरिक एसिड

यूरिक एसिड का बढ़ना आम समस्या नहीं है। अगर समय रहते इसको काबू में न किया जाए तो यह दर्द को बढ़ा देता है। ऐसे में हम आपको बिना दवाइयों और किसी अन्य उपाय के अलावा ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है। आप अगर यह योगासन कर लें तो आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है।

सर्दियों में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आम हो जाती है। कई लोग यूरिक एसिड बढ़ने से होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वह लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं। हालांकि दवाईयों का सेवन करने के बावजूद उन्हें इससे राहत नहीं मिलती।

सर्दियों में यूरिक एसिड की तकलीफ रात भर की नींद को उड़ा देती है। अब ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जो आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए काफी हद तक मदद करेंगे। अगर आप नियमित इन योगासन को करते हैं तो आपको यूरिक एसिड से बहुत जल्दी आराम मिल सकता है।

सुबह उठते ही योगासन करने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यहां 4 योगासन हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकते हैं।

वृक्षासन (ट्री पोज): योग में यह आसन शरीर को संतुलित करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है। वृक्षासन या ट्री पोज एक तरह से खड़े होकर किए जाने वाला योगासन है। यह आसन संतुलन, स्थिरता और ध्यान को बढ़ाता है। यह एक प्रतिष्ठित योग मुद्रा है जो हठ योग से अपनी जड़ें लेती है।

पवनमुक्तासन (विंड रिलीजिंग पोज): यह आसन पाचन तंत्र को सुधारने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है। बता दें कि सबसे पहले जमीन पर मैठ बिछा लें और उसपर पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने घुठने को मोड़े और उसे छाती पर ले आएं। ठीक ऐसे ही बाएं घुठने को भी छाती के करीब ले आएं। इससे आपको यूरिक एसिड कम करने में काफी मदद मिलेगी।

भुजंगासन (कोबरा पोज): आसन मेरुदंड को मजबूत करने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है।

शलभासन (ग्रासहॉपर पोज): यह आसन पाचन तंत्र को सुधारने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है।

इन योगासनों को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिएः

- सुबह उठते ही खाली पेट योगासन करें।
- योगासनों को धीरे-धीरे और सावधानी से करें।
- यदि आपको कोई चोट या बीमारी है, तो योगासनों को करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
- योगासनों के अलावा, स्वस्थ आहार और जीवनशैली का पालन करें।

दिल्ली की इस सीट पर दल-बदलुओं की होगी सीधी जंग, आप-कांग्रेस ने लगाई जीत की हैट्रिक; बीजेपी के लिए टफ फाइट

पटेल नगर विधानसभा सीट दिल्ली चुनाव में दल–बदलुओं की जंग का गवाह रही है। भाजपा कांग्रेस और आप सभी दलों के लिए पाला बदलना और पुरानी पार्टी पर आरोप लगाना आम बात रही है। इस बार भी राजकुमार आनंद और प्रवेश रतन जैसे नेताओं ने पार्टी बदली है। ऐसे में पटेल नगर सीट पर कौन बाजी मारेगा यह देखना दिलचस्प होगा।

नई दिल्ली। पटेल नगर विधानसभा सीट (Patel Nagar Vidhan Sabha Seat) से चुनाव लड़ने वाले पार्टियों के खेवनहार ही पलटवार कर देते हैं। पाला बदलने और पुरानी पार्टी पर तोहमत मढ़ने का सिलसिला भाजपा, कांग्रेस और आप के लिए एक जैसा रहा है।

अक्टूर 2022 में बौद्ध महासभा में दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी-देवताओं के मूर्ति पूजा के विरोध के विवादों में आए तो दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुईं।

राजकुमार आनंद ने AAP का छोड़, भाजपा का पकड़ा दामन

अनुसूचित जाति से आने वाले गौतम पार्टी में बड़ा चेहरा थे और पार्टी को संकट में फंसा देख उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पाले में मजबूती से खड़ा रखने के लिए आप की सरकार ने पटेल नगर से विधायक व अनुसूचित जाति से आने वाले पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद को खेवनहार के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया।

लेकिन, इस वर्ष लोकसभा चुनाव के समय ही आनंद ने आप छोड़ने का एलान करने के साथ पार्टी पर अनुसूचित जाति विरोधी होने की तोहमत मढ़ दी। बाद में भाजपा के दामन थाम लिया। ऐसे ही पटेल नगर से भाजपा के टिकट पर वर्ष 2020 में चुनाव लड़ चुके जाटव समाज से आने वाले प्रवेश रतन इसी साल पाला बदलकर आप में चले गए और अब वे पार्टी के प्रत्याशी भी हैं।

सुरक्षित सीट पटेल नगर में जाटव समाज के नेताओं और मतदाताओं का दबदबा रहा है। लेकिन, पाला बदलकर दाव आजमाने के लिए यह सीट बड़ा चुनावी रण क्षेत्र है। राजकुमार आनंद, प्रवेश रतन के अलावा यहां से कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ ने भी ऐसा ही किया था।

दिल्ली में कमजोर पड़ रही कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने वर्ष 2015 में इस सीट पर भाजपा की तरफ से किस्मत आजमाया, लेकिन आप के हजारी लाल चौहान बड़े अंतर से मात दी। अगले चुनाव 2020 में कृष्णा फिर से कांग्रेस में लौटीं और इस सीट पर दोबारा किस्मत आजमाया, लेकिन परिणाम उससे भी खराब रहा और वो तीसरे स्थान पर रहीं।

एक बार कमल, तीन बार पंजा और अब तीन बार से झाड़ू का जोर

पटेल नगर विस क्षेत्र से 1993 में भाजपा के एमआर आर्या के हाथ पहली बाजी लगी। उसके

पटेल नगर सीट

वर्ष	विजेता	पार्टी	कितने वोट से जीते
1993	एमआर आर्या	भाजपा	2147
1998	रमाकांत गोस्वामी	कांग्रेस	5594
2003	रमाकांत गोस्वामी	कांग्रेस	14176
2008	राजेश लिलोथिया	कांग्रेस	14176
2013	वीणा आनंद	आप	6262
2015	हजारी लाल चौहान	आप	34663
2020	राजुकमार आनंद	आप	30935

बाद 1998, 2003 व 2008 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने परचम लहराया। इसमें लगातार दो बार कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी ने जीत दर्ज की।

वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ यहां राजकुमार आनंद की पत्नी वीणा आनंद आप के टिकट पर जीत दर्ज की। तब से हर चुनाव में आप के टिकट पर चेहरे बदलते रहे, लेकिन दबदबा झाड़ू का ही रहा। वर्ष 2020 चुनाव से पहले पत्नी के बाद राजकुमार ने आप ज्वाइन की और पटेल नगर से विधायक चुने गए।

राजकुमार आनंद इसी साल आप छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में चले गए और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे, लेकिन वे महज 0.66 प्रतिशत ही वोट पा सके। यानी पटेल नगर विधानसभा में भी बुरी तरह पीछड़े और तीसरे नंबर पर रहे।

बंगाली मार्केट की मिठाई से लेकर तंदूर के मुगलई खाने के शौकीन थे मनमोहन सिंह, दिल्ली से जुड़ी थी खास यादें

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी दिल्ली से जुड़ी यादें ताजा हो रही हैं। किताबों और खाने के शौकीन मनमोहन सिंह को दिल्ली की पाक कला में खास दिलचस्पी थी। कमला नगर के कृष्णा स्वीट्स के डोसा दरियागंज में तंदूर के मुगलई खाने मालचा मार्ग पर फुजिया के चाइनीज और बंगाली मार्केट की मिठाइयां उन्हें खास पसंद थीं।

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनके लिए दिल्ली एक ऐसा शहर था, जहां उन्हें किताबों, खाने और परिवार के साथ आनंद मिलता था। मनमोहन सिंह व्यस्त समय से अपने और परिवार के लिए अलग से कुछ पलों को संजोकर रखते थे और अपने प्रियजनों के साथ किताबों की दुकानों और मशहूर खाने-पीने की दुकानों में समय व्यतीत करते थे।

मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपने संस्मरण स्ट्रिक्टली पर्सनल में इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे रोमांचक यात्राएं किताबों की दुकानों पर होती थीं। इसमें कश्मीरी गेट में रामकृष्ण एंड संस, कनाट प्लेस में गलगोटिया और न्यू बुक डिपो में अपने परिवार के साथ घंटों बिताते थें। लेकिन दिल्ली की पाक कला में उनकी अलग दिलचस्पी थी।

कमला नगर के कृष्णा स्वीट्स के डोसा का उठाया था लुत्फ

मनमोहन सिंह की बेटी ने अपने संस्मरण में बताया कि हर दो माह में हम पहले से तय जगहों पर खाने के लिए जाते थे। इसमें दक्षिण भारतीय भोजन के लिए कमला नगर में कृष्णा स्वीट्स के डोसा और इडली का लुत्फ उठाया करते थे, मुगलई खाने के लिए दरियागंज में तंदूर, चाइनीज के लिए मालचा मार्ग पर फुजिया और मिठाई के लिए बंगाली मार्केट जाया करते थे।

लगभग तीन साल पहले हुआ था आखिरी बार टेकअवे

फुजिया के मालिक मनप्रीत सिंह ने बताया कि पहले मनमोहन सिंह अक्सर हमारे रेस्तरां में आते थे। उन्हें खास तौर पर गर्म और खट्टे सूप और स्प्रिंग रोल पसंद थे। बच्चों को अमेरिकी चापसुई बहुत पसंद थी। वे घर पर डिलीवरी के लिए खाना लेने के लिए किसी को भेजते थे। आखिरी बार टेकअवे लगभग तीन साल पहले हुआ था और वे आखिरी बार वर्ष 2007 में आए थे।

संदेश और रसगुल्ला जैसी मिठाइयां मनमोहन सिंह को थी पसंद

उनके रेस्तरां की तरफ से बताया गया कि यही नहीं उनके राहुल गांधी भी अक्सर आते हैं, लेकिन उनकी निजता को ध्यान में रखते हुए वे फोटो नहीं लेते। भीमसेन बंगाली स्वीट हाउस के मालिक जगदीश अग्रवाल ने कहा कि मनमोहन सिंह का परिवार अक्सर हमारी दुकान पर आता था। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को मिठाई बहुत पसंद थी। संदेश और रसगुल्ला जैसी मिठाइयां उन्हें पसंद थीं।

आम आदमी पार्टी ने डॉ. मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की, केजरीवाल-आतिशी ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर आम आदमी पार्टी (आप) ने उन्हें शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा।

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर आम आदमी पार्टी (आप) ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा। वो सदैव ही सभी लोगों से बेहद विनम्रता से मिलते थे। डॉ. मनमोहन सिंह जी भारत रत्न के हकदार हैं। प्रभु उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 1990 के दशक में भारत के परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की गहन विरासत वाले एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री का देहावसान हो गया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, मनमोहन सिंह की खास विशेषता यह थी कि उनमें अटूट अखंडता और इस देश के लोगों और उनकी प्रगति के प्रति उनमें गहरी प्रतिबद्धता थी।

उन्होंने लिखा- हमारी आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने आधुनिक भारत को ऐसे आकार दिया है जो आने वाली सभी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उसकी आत्मा को शांति मिलें।

दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके परिवार से मिला और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। डॉ. सिंह एक दूरदर्शी नेता थे जिनके आर्थिक सुधारों ने आधुनिक भारत को आकार दिया और जिनकी विनम्रता ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

मनीष सिसोदिया ने कहा- देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का जाना एक युग का अंत है। उनका सादगी और सेवा से भरा जीवन हमें हमेशा प्रेरित करेगा। यह देश के लिए एक गहरा दुख है, जिसे भर पाना कठिन है। देश उनके योगदान और त्याग को कभी नहीं भुला सकेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति और परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति, इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के रूप में हमेशा याद रखेगा- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 27 दिसंबर आम आदमी पार्टी ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शुक्रवार को ₹आप₹ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पवित्र क्षण में उनके परिवार से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। डॉ. सिंह एक दूरदर्शी नेता थे। उनके आर्थिक सुधारों ने आधुनिक भारत को आकार दिया और उनकी विनम्रता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर कहा कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वह एक शानदार अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों को दिशा दी और देश के इतिहास में एक अहम मोड़ पर उसकी दिशा तय की। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नेतृत्व क्षमता शांति, ईमानदारी और देशवासियों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से परिपूर्ण थी। डॉ. सिंह के योगदान ने हमारे आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम पर गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

उधर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह भारत के महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दस साल प्रधानमंत्री रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके निधन का समाचार निश्चित रूप से देश के लिए एक दुखद घटना है। एक अपूरणीय क्षति है। इतिहास उन्हें हमेशा एक महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से स्वर्गीय मनमोहन सिंह उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।

संजय सिंह ने कहा कि मुझे राज्यसभा में मनमोहन सिंह के साथ इतने सालों तक रहने का सौभाग्य मिला। मैं एक घटना भूल नहीं पाता हूं, एक बार मैं हस्ताक्षर कर रहा था, वह पीछे खड़े थे। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा । मैंने पलट कर देखा तो मनमोहन सिंह थे। मैंने उनके पैर छुए और माफी मांगी कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय सिंह आप विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। मैं उनके यह वाक्य कभी नहीं भूल सकता। वह बहुत प्यार से लोगों से मिलते थे। वह जब भी सदन में कुछ भी बोलने के लिए खड़े होते थे तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। आज एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह निश्चित रूप से इस योग्य हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने दस साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनकी पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में उनका बहुत सम्मान था। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए।

तफ़हीमुल क़ुरआन (हिन्दी) ऐप का विमोचन

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आज यहाँ जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के मुख्यालय में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के प्रसिद्ध तफसीर (व्याख्या) तफ़हीमुल क़ुरआन (हिन्दी) ऐप का विमोचन समारोह जमाअत के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द से जुड़ी संस्था 'इस्लामी साहित्य ट्रस्ट' ने इस ऐप को विकसित किया है।

जमाअत के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ट्रस्टियों और ऐप डेवलपर यूसुफ अमीन को बधाई देते हुए कहा कि मौलाना मौदूदी ने तफ़सीर लिखने में बहुत मेहनत की है। तफ़हीमुल क़ुरआन की तैयारी के संदर्भ में मौलाना मौदूदी ने जर्मन भाषा सीखी, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की बुनियादी पुस्तकों का अध्ययन किया, अन्य विचारों और सिद्धांतों का गंभीर मूल्यांकन करने के पश्चात तफसीर (व्याख्या) तैयार किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे इस्लामी साहित्य ट्रस्ट द्वारा किया गया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे जितना संभव हो उतना लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें, ताकि यह न केवल मुसलमानों तक पहुंच सके, बल्कि हिंदी जानने वाले हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके।

ट्रस्ट के सचिव वारिस हुसैन द्वारा परिचयात्मक उद्बोधन के उपरांत जमाअत के अमीर एवं अन्य पदाधिकारियों ने ऐप का पोस्टर जारी किया। फिर अमीर जमाअत ने इसके लिंक पर क्लिक करके ऐप लॉन्च किया। ऐप डेवेलपर युसूफ अमीन ने इसके सभी फीचर्स से परिचय कराया। इस ऐप में पवित्र क़ुरआन का संपूर्ण पाठ, उसका हिंदी अनुवाद और तफ़हीमुल क़ुरआन का अनुवाद शामिल है। अनुवाद और व्याख्या दोनों पढ़े जा सकते हैं, लेकिन सुनने का विकल्प केवल अनुवाद के लिए है।

तफ़हीमुल क़ुरआन का हिंदी अनुवाद मौलाना नसीम अहमद गाजी फलाही ने किया है। इस मौके पर नसीम गाजी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि 6 वॉल के इस तफ़सीर के अनुवाद में लगभग 12 वर्ष लगे। उन्होंने बताया कि अनुवाद के साथ इसमें क़ुरआन की शब्दावली की संक्षिप्त व्याख्या और पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) की हदीसों के संदर्भ भी शामिल किए गए हैं।

इस कार्यक्रम में इमारत -ए-शरिया बिहार के पूर्व नाजिम (प्रबंधक) एवं ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी भी उपस्थित थे। उन्होंने अनुवाद के काम की संवेदनशीलता के बारे में बात करते हुए इस काम से जुड़े लोगों को बधाई दी।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के शरिया काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव डॉ. रज़ी-उल-इस्लाम नदवी ने कहा, ₹मेरा मानना है कि यह काम एक सदक़ा-ए - जारिया (सदैव शेष रहने वाला पुण्य का कार्य) है। वे सभी जिन्होंने इसमें किसी न किसी तरह से योगदान दिया है, पुरस्कार के पात्र हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने भी इस कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और ट्रस्टियों को बधाई दी। ट्रस्ट के अध्यक्ष फरहत हुसैन ने कहा कि इस ऐप में तल्खीस (संक्षिप्त व्याख्या) तफ़हीमुल क़ुरआन जिसे मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही ने तैयार किया था, जिसका हिंदी में अनुवाद मौलाना कौसर यजदानी नदवी ने किया है, को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने धार्मिक पुस्तकों को भी डिजिटल रूप में लाने की योजना बनाई है।

इस ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस पर इंस्टॉल किया जा सकता है।इसे प्ले स्टोर पर जाकर तफहीमुल कुरान हिंदी टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है या निम्नलिखित लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

50 प्रतिशत मरीजों में पैंक्रियाज की बीमारी का कारण बन रहा अल्कोहल, जानें बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह

गॉल ब्लाडर में स्टोन होने पर सर्जरी करा चुके मरीजों में दोबारा बीमारी होने की आशंका सिर्फ पांच प्रतिशत रहती है। सर्जरी नहीं होने पर बीमारी दोबारा होने की आंशका 20 प्रतिशत तक रहती है। अल्कोहल व धूपमान का सेवन जारी रखने वाले मरीजों को बीमारी दोबारा होने की आशंका 70–80 प्रतिशत होती है। सेवन बंद कर देने से जोखिम घटकर 10–15 प्रतिशत रह जाती है।

नई दिल्ली। पैंक्रियाज की बीमारी (पैंक्रियाटाइटिस) के करीब 50 प्रतिशत मरीजों में बीमारी का कारण अल्कोहल का सेवन बन रहा है। पहले दस से 15 प्रतिशत मरीजों में अल्कोहल इस बीमारी का कारण बनता था। एम्स के गैस्ट्रालाजी के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद गर्ग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह गलत धारणा है कि पैंक्रियाटाइटिस ठीक नहीं हो सकता है। यह लाइलाज नहीं है लेकिन शराब व धूमपान का सेवन छोड़ना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत मरीजों में पैंक्रियाटाइटिस का कारण गॉल ब्लाडर में स्टोन होना होता है। कुछ मरीजों के जीन में म्युटेशन, आनुवांशिक, दवा का दुष्प्रभाव इत्यादि अन्य कारण होते हैं। पैंक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित 80 प्रतिशत मरीजों में हल्की बीमारी होती है। 20 प्रतिशत मरीजों में गंभीर बीमारी होती है, जिन्हें परेशानी अधिक होती है। इलाज के बाद 30-40 प्रतिशत में मरीजों में बीमारी दोबारा हो जाती है।

दोबारा बीमारी होने की आशंका सिर्फ पांच प्रतिशत

गॉल ब्लाडर में स्टोन होने पर सर्जरी करा चुके मरीजों में दोबारा बीमारी होने की आशंका सिर्फ पांच प्रतिशत रहती है। सर्जरी नहीं होने पर बीमारी दोबारा होने की आंशका 20 प्रतिशत तक रहती है। अल्कोहल व धूपमान का सेवन जारी रखने वाले मरीजों को बीमारी दोबारा होने की आशंका 70-80 प्रतिशत होती है। सेवन बंद कर देने से जोखिम घटकर 10-15 प्रतिशत रह जाती है।

पैंक्रियाटाइटिस दोबारा होने पर भी चार से पांच दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर मरीजों को वर्ष भर में तीन से चार बार पैंक्रियाइटिस अटैक होता है। इसलिए वर्ष भर में 15-20 दिन परेशानी होती। बाकी 345-350 दिन मरीज ठीक रहते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एम्स में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि 20 से 25 मरीजों को क्रोनिक पैंक्रियाइटिस होती है।

कुच मरीजों में भोजन पचाने की क्षमता होती है कम

इन मरीजों को लंबे समय तक पेट में दर्द रहता है। 35-40 प्रतिशत मरीजों को डायबिटीज, कुछ मरीजों को पैंक्रियाज से एंजाइम कम बनने से भोजन पचाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे वजन कम हो जाता है। एम्स में हुए अध्ययन में पाया गया है कि इलाज से 80 प्रतिशत मरीजों का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। 20 प्रतिशत मरीजों को दर्द से छुटकारा पाने में तीन-पांच वर्ष तक समय लग जाता है।

खानपान में नहीं करना होता खास परहेज

उन्होंने बताया कि मरीजों को खानपान में कुछ खास परहेज नहीं करना होता है। घर का बना साफ सुथरा शाकाहारी भोजन लेने की सलाह दी जाती है। अलग से अतिरिक्त पोषण की जरूरत नहीं होती। यह ध्यान रखना जरूरी है कि लंबे समय तक भूखे न रहें। अधिक देर तक भूखे रहने से बीमारी दोबारा होने की आशंका बढ़ जाती है। दिन में चार बार थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए।

जनपद में आपदा को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का हुआ अयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा : दिनाक़ 27 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से रूपम सिनेमा हॉल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा की वार्डन पोस्ट संख्या स्थित गोकुल बेराज औरंगाबाद के घाट पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के साथ मिलकर एक राज्य स्तरीय मेगा आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन जिला अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे, अपर जिला अधिकारी नमामि गंगे प्रभारी नागरिक सुरक्षा राजेश यादव, के नेतृत्व मे नागरिक सुरक्षा मथुरा के उप नियंत्रक मुनेश कुमार गुप्ता एवं सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह, आपदा विशेषज्ञ सुशील कुमार, के द्वारा मॉक ड्रिल कार्यक्रम को सफ़ल बनाने की जिम्मेदारी दी गई जिसमें पोस्ट वार्डन एवं आपदा मित्र अशोक यादव जो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नागपुर एवं राज्य आपदा मोचन बल लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको गोकुल बेराज औरंगाबाद घाट की जिम्मेदारी दी गई जिसमें एन डी आर एफ के और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर पांच लोगों को जो नाव पलटने से यमुना नदी में गिर गए थे उनको सी पी आर की मदद से एवं फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई गई। इसी के साथ सिविल डिफेंस मथुरा के उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह ने बताया कि रूपम सिनेमा हॉल में अचानक आग लगने की ख़बर मिलते ही सिविल डिफेंस मथुरा अपने दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंच कर अग्निशमन विभाग के साथियों के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया रूपम सिनेमा हॉल में फसे हुए आठ घायल लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी जिला हॉस्पिटल मथुरा में घायलों को भर्ती कराया गया बही दूसरी तरफ गोकुल बेराज औरंगाबाद पर भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें बीस आपदा मित्रों एवं सिविल डिफेंस मथुरा के चीफ वार्डन राजीव अग्रवाल डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल सीनियर स्टॉफ ऑफिसर दीपक चतुर्वेदी बैंकर एस डी आर एफ से मेजर अलवेंदर सिंह , डिप्टी पोस्ट वार्डन विकास सोनी,सैक्टर वार्डन राम सैनी, शुभम्‌कुमार, पवन प्रकाश, राजेश कुमार,पवन शर्मा, चरन सिंह, जीतेश, गुलशेर, सोहन लाल, मुकेश शर्मा, गोविंद, नरेन्द्र, हेमंत, यतेंद्र, विक्रम, राजेंद्र पंकज गर्ग, नरेश अग्रवाल, जितेन्द्र कुमार धनगर, रोहित कुशवाह, साहिद बाबू, ऋषभ, धर्मेन्द्र तोमर, शैलेश खण्डेलवाल, प्रमोद यादव,रावेंद्र बंसल, सुनैना, डॉ महेश चन्द एव एसडीआरएफ, तहसीलदार महावन,फायर विभाग, मेडिकल टीम, ट्रेफिक पुलिस, और थाना महावन प्रभारी सभी लोगो ने मेगा मॉक ड्रिल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

शादीशुदा गर्लफ्रेंड को भगाने का था प्लान, कार में बैठे ही थे; ससुरालवालों को लगी भनक और फिर...

परिवहन विशेष न्यूज

एक विवाहिता महिला के प्रेमी को उसके ससुराल वालों ने कमरे में बंधक बनाकर पीटा। प्रेमी को कार में बिठाकर प्रेमिका को लेकर भागने के प्रयास में था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रेमी को छुड़ाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर के माध्यम से पढ़िए पूरा माजरा क्या है?

दनकौर (नोएडा)। कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता प्रेमिका से मिलने आए अलीगढ़ जिले के प्रेमी को कमरे में बंधक बनाकर पीटने व पुलिस द्वारा मुक्त कराने का मामला सामने आया है। आरोपित प्रेमी कार में बिठाकर प्रेमिका को लेकर भागने के प्रयास में था।

इसी दौरान प्रेमिका के ससुरालीजन ने उसे दबोच लिया। पिटाई से घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, अतरौली ग्राम के युवक का अलीगढ़ की युवती से वर्षों से प्रेम प्रसंग था।

प्रेमी, प्रेमिका के ससुराल से कुछ दूर मिलने पहुंचा

युवती की 10 माह पहले दनकौर क्षेत्र के गांव में शादी हुई है। फिर भी दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। बृहस्पतिवार की सुबह महिला के कहने पर प्रेमी कार में एक दोस्त के साथ उसकी ससुराल में घर से कुछ दूर पहुंचा। वहां महिला कार में आकर बैठ गई।

इस बीच सूचना पर ससुरालीजन पहुंचे व कार को रुकवाकर प्रेमी समेत दोनों की पिटाई की। आरोपित के दोस्त को छोड़ दिया। इसके बाद दोबारा प्रेमी को कमरे में बंधक बनाकर पीटा। किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी।

पुलिस ने लड़के को छुड़ाया

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराकर घायलावस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि युवक ज्यादा घायल नहीं है। हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है। लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।

पुलिस पूछताछ में गिरोह ने किए कई बड़े खुलासे

वहीं पर दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में नौ सालों से सक्रिय एक लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह शादी के इच्छुक लोगों को शिकार बनाने में खासी मशक्कत करता था। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की युवती को शादी और रुपयों का लालच देकर गिरोह में शामिल किया गया।

लेकिन युवती ने गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए खुद ही पुलिस से शिकायत कर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बृहस्पतिवार को लुटेरी दुल्हन गिरोह का फर्दाफाश किया। पूछताछ में गिरफ्तार गिरोह के चार सदस्यों ने कई चौंकाने वाली बातें कहीं।

बिना लाइसेंस शराब परोसने के मामले में नोएडा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, कई गिरफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में रेस्टोरेंट फार्म हाउस और बार में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है। आबकारी विभाग की कार्रवाई में लापरवाही और चोरी उजागर हो रही है। विभाग को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इस साल आठ से ज्यादा जगहों पर बिना लाइसेंस के शराब परोसने के मामले पकड़े गए हैं।

नोएडा। जिले में रेस्त्रां, फार्म हाउस, और बार में बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही है। आबकारी विभाग की कार्रवाई में लापरवाही और चोरी उजागर हो रही है। इससे विभाग को राजस्व भी चूना लग रहा है। इसकी बानगी आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के मामले में देखा जा सकता है।

इस साल आबकारी विभाग आठ से ज्यादा जगह पर बिना लाइसेंस शराब परोसने के मामले पकड़ चुका है। जानकारों की मानें तो नोएडा के डूब क्षेत्र में चलने वाले फार्म हाउस में चोरी छिपे पार्टियों का आयोजन किया जाता है।

इन पार्टियों में बिना लाइसेंस लिये ही शराब को परोसा जाता है। यहां तक शराब दूसरे राज्यों से लाई जाती है। हरियाणा और दिल्ली की शराब तक पकड़ी जा चुकी है। यहां तक माल में चल रहे रेस्त्रा में भी नियमों को ताक पर रखने में गुरेज नहीं है।

सुबोध कुमार

केस नंबर एक

क्यूआर कोड हटाकर खपाई जा रही शराब

आबकारी विभाग की टीम ने एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर 135 स्थित सिद्दकी फार्म हाउस ग्रीन ब्यूटी में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि वह दिल्ली से शराब

लाकर परोस रहे थे। रुपये बचाने के चक्कर में शराब के बोतल पर लगे क्यूआर कोड को हटा देते हैं। जिससे पकड़ में नहीं आएं। जांच के दौरान आरोपित टीम को एफएफ-11 बार लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए थे।

केस नंबर दो

मॉल के रेस्त्रा में पकड़ी थी चोरी

पांच नवंबर को आबकारी विभाग और सेक्टर 142 थाना की संयुक्त टीम ने सेक्टर 92 स्थित अल्फाथंब माल के धमक रेस्त्रा में छापा मारा था। रेस्त्रा में बिना लाइसेंस के तीन लोगों को शराब परोसते हुए पकड़ा था। पुलिस टीम ने 102 विदेशी मदिरा और बीयर की 315 केन व बोतल पकड़ी थीं।

इनमें बिग बेन, बकार्डी वाइट रम, रायल स्टैग, जैगरमेस्टर, जैकब्स क्रीक, जान स्टोन, सुलावाइन, ट्यूबोर्ग, बडवाइजर आदि ब्रांड की शराब शामिल थी।

लाइसेंस की पड़ती है जरूरत

आबकारी अधिकारी मुताबिक के लिए कहीं पर भी शराब परोसने से पहले लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यहां तक की किसी भी समारोह में भी शराब परोसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। यह स्थाई और अस्थाई दोनों होता है। विभाग की ओर रेस्त्रा, बार व फार्म हाउस को एफएल-सात लाइसेंस दिया जाता है जबकि समारोह बार के लिये एफएल-11 लाइसेंस दिया जाता है।

इनके लिये जरूरी है लाइसेंस

उत्सव

क्लब या सोसायटी क्लब

रिजॉर्ट

फार्म हाउस

मैरिज हॉल

भूकंप और आग से बचाव का क्या है मनमोहन सिंह से कनेक्शन, पूर्व सेनाध्यक्ष ने बातचीत में किया खुलासा

डॉ. मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी नेता और कुशल अर्थशास्त्री थे। उनके कार्यकाल में देश ने आर्थिक रूप से प्रगति की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। इस प्राधिकरण ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनरल एनसी विज ने दैनिक जागरण से बातचीत में डॉ. मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व और उनके कार्यों की सराहना की।

गुरुग्राम। जाने माने अर्थशास्त्री व पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरलता, सौम्यता व सादगी के प्रतीक थे। वह दूरद्रष्टा थे। बहुत आगे की सोचते थे। सेना की मजबूती से लेकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर वह प्रयासरत रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन उनके शासनकाल में ही हुआ। आज यह प्राधिकरण देश की सुरक्षा में विशेष भूमिका निभा रहा है। ये बातें डॉ. मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान सेनाध्यक्ष व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वाइस प्रेसिडेंट रहे जनरल एनसी विज ने दैनिक जागरण से फोन पर बातचीत कही। उन्होंने कहा कि डा. मनमोहन सिंह से जब भी बातचीत करता था तो कुछ न कुछ नई जानकारी मिल जाती थी। वह सही मायने में विद्वान थे। उनकी विद्वता की कोई सीमा नहीं थी। हर क्षेत्र की गहरी जानकारी उन्हें थी। बातचीत के दौरान किसी भी विषय पर इतना कुछ कह जाते थे जैसे कि वे हर विषय के विशेषज्ञ हों। सेना की मजबूती की बात वह हमेशा किया करते थे। वह नई तकनीकी को विकसित करने पर हमेशा जोर देते थे।

मनमोहन सिंह का निधन- प्रोफेसर से योजना आयोग अध्यक्ष,आरबीआई गवर्नर तक- वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री तक निर्विवाद पारदर्शी नेतृत्व

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर 26 दिसंबर 2024 को रात्रि करीब 10 बजे दुनियाँ का सबसे अलग अभूतपूर्व छवि के धनी, बेदांग व पारदर्शी व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर पूरी दुनियाँ आवक रह गई। एम्स से जारी बुलेटिन के अनुसार रात्रि 9.51 बजे उनका निधन हुआ जो रात्रि 8.02 को एम्स में भर्ती हुए थे परंतु डॉक्टरों के भूतपूर्व प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका जो कि 92 वर्ष की उम्रदराज अस्वस्थता की बीमारी से ग्रस्त थे। निधन की सूचना प्राप्त होते ही राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से लेकर पूरे केंद्रीय मंत्रियों व विपक्षी पार्टियों से लेकर आम आदमीयों तक का श्रृद्धाजंलियों का सैलाब उमड़ पड़ा सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द करते हुए 7 दोनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा करने में देर नहीं लगाई व 28 सितंबर सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर शोक प्रस्ताव पारित करने की खबरें आ रही है, तो कांग्रेस ने भी अपने सभी कार्यक्रम 7 दिनों के लिए रद्द कर दिए हैं। इधर तेलंगाना सरकार सहित कुछ ने सरकारी कार्यालय व शैक्षणिक संस्थाएं शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 को बंद रखने व 7 दोनों का राष्ट्रीय शोक मनाने का आदेश पारित किया है। उनके पार्थिव शरीर को 3 जनपद उनके निवास स्थान पर लाया गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री व एम्स के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी सबसे पहले एम्स पहुंचे हुए पूरी प्रक्रियाओं की देखरेख की व पारिवारिक सदस्यों से परामर्श के बाद पार्थिव शरीर को उनके 3 जनपद रोड रवाना किया गया क्योंकि पूर्व पीएम के निधन से देश को अपूर्णिय क्षति हुई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सैल्यूट,देश को अपूर्णिय छति- दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास।

साथियों बात अगर हम पूर्व पीएम के निधन की करें तो, आर्थिक सुधारों के प्रणेता पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात यहां निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। एम्स दिल्ली ने सिंह के निधन की घोषणा की, उन्हें गंभीर हालत में रात करीब साढ़े आठ बजे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था।पूर्व पीएम के निधन की जानकारी देते हुए एम्स अस्पताल ने बयान जारी किया है।अस्पताल ने कहा कि उन्हें 26 दिसंबर की शाम को ही उस वक्त लाया गया, जब वह घर में बेहोश होकर गिर गए थे। उन्हें घर पर ही प्राथमिक इलाज दिया गया और फिर एम्स कीइमरजेंसी में लाया गया। उन्हें सभी प्रयासों के बाद भी बचाया नहीं जा सका और रात को 9:51 पर उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से आयु जनित बीमारियों से जूझ रहे थे। एक अर्थशास्त्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर उन्होंने देश की सेवा की थी. रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पद पर रहे डॉ मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी।

साथियों बात अगर हम पूर्व पीएम के साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड व शिक्षण करियर की करें तो, वे साल 2004 से 2014 तक भारत के पीएम रहे। वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहें, डॉ मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जाने वाले पहले प्रधान मंत्री भी थे.डॉ मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब, ब्रिटिश भारत (अब पंजाब, पाकिस्तान) में एक सिख परिवार में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर हुआ था. जब वह बहुत छोटे थे, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी,उनकी नानी ने उनका पालन-पोषण किया और वह उनसे बहुत करीब थी। साल 1947 में विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया था, भारत के विभाजन के बाद, उनका परिवार हल्द्वानी, भारत में चला गया,1948 में वे अमृतसर चले गए, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज, अमृतसर में अध्ययन किया, उन्होंने पंजाब

विश्वविद्यालय, फिर होशियारपुर में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 1952 और 1954 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की, अपने शैक्षणिक जीवन में प्रथम स्थान पर रहे।उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र ट्रिपोस पूरा किया. वे सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य थे.डी फिल. पूरा करने के बाद सिंह भारत लौट आए। वे 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। साल 1959 और 1963 के दौरान,उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया और 1963 से 1965 तक वे वहाँ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे।1966 से 1969 तक यूएनसीटीएडी में किया था कामवे 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम करने चले गए, बाद में, अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देते हुए ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया।1969 से 1971 तक, सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉ मनमोहन सिंह ने 1966-1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया, इसके बाद उन्होंने अपना नौकरशाही करियर तब शुरू किया जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर किया था काम1970 और 1980 के दशक के दौरान मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-1976), रिजर्व बैंक के गवर्नर (1982-1985) और योजना आयोग के प्रमुख (1985- 1987)1972 में, सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने और 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव 1980- 1982 में वे योजना आयोग में थे, और 1982 में, उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक इस पद पर रहे.वे 1985 से 1987 तक योजना आयोग (भारत) के उपाध्यक्ष बने. योजना आयोग में अपने कार्यकाल के बाद, वे 1987 से नवंबर 1990 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक, साउथ कमीशन के महासचिव थे।मनमोहन सिंह नवंबर 1990 में जिनेवा से भारत लौट आए और चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधान मंत्री के सलाहकार के रूप में पद संभाला।मार्च 1991 में, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने.पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बने थे वित्त मंत्रीसाल 1991 में, जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, नव निर्वाचित प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गैर-राजनीतिक सिंह को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, हालांकि ये उपाय संकट को टालने में सफल साबित हुए और वैश्विक स्तर पर सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, लेकिन 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जून 1991 में, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना.साल 2004 में बने देश के प्रधानमंत्री इसके बाद, 1998-2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सिंह राज्यसभा (भारत की संसद के ऊपरी सदन) में विपक्ष के नेता थे। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई, तो इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद सिंह को सौंप दिया. उनके पहले मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानून और परियोजनाएं क्रियान्वित कीं।2008 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के विरोध के कारण वाम मोर्चा दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार लगभग गिर गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उन्होंने 2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर होने का विकल्प चुना। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 1991 से 2019 तक असम राज्य और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया. मनमोहन सिंह ने 1958 में गुरशरण कौर से शादी की, उनकी तीन बेटियां हैं।

साथियों बात अगर हम पूर्व पीएम के राजनीतिक घटनाक्रम की करें तो,1991-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए भारतके राज्यपाल।1991 केंद्रीय वित्त मंत्री और बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए1990 : आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधान मंत्री के सलाहकार।1987: महासचिव और आयुक्त, दक्षिण आयोग जिनेवा।1985 : उपाध्यक्ष, योजना आयोग।1985 : अध्यक्ष, भारतीय आर्थिक संघ।1983 : सदस्य, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद।1982 : भारत के लिए वैकल्पिक गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईएमएफ।1982 : गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।1980 :अध्यक्ष, भारत- जापान संयुक्त अध्ययन समिति की भारत समिति।1980 : सदस्य-सचिव, योजना आयोग।1976 : सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग), भारत सरकार। सदस्य, वित्त परमाणु ऊर्जा आयोग 1991 : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए भारत के राज्यपाल।1991 : केंद्रीय वित्त मंत्री और बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए।1990 : आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधान मंत्री के सलाहकार।1987 : महासचिव और आयुक्त, दक्षिण आयोग, जिनेवा।1985 : उपाध्यक्ष, योजना आयोग।1985 : अध्यक्ष, भारतीय आर्थिक संघ।1983 : सदस्य, प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद।1982 : भारत के लिए वैकल्पिक गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईएमएफ।1982 : गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।1980 : अध्यक्ष, भारत-जापान संयुक्त अध्ययन समिति की भारत समिति।1980 : सदस्य -सचिव, योजना आयोग।1976 : सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग), भारत सरकार। सदस्य, वित्त, परमाणु ऊर्जा आयोग।1972 : मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत।1971 : आर्थिक सलाहकार, विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत। पूर्व इतिहास1966: उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मनमोहन सिंह का निधन- प्रोफेसर से योजना आयोग अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर तक- वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री तक निर्विवाद पारदर्शी नेतृत्व,पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन की खबर से देश-विदेश से अश्रुपूर्ण श्रृद्धाजंलियों का सैलाब उमड़ा-7 दिन का राष्ट्रीय शोक- सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द।दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सैल्यूट- देश को आपूर्णिय छति- दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास

एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Maruti e-Vitara, नजर आए ADAS जैसे फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति ई–विटारा को आगामी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया जाएगा। इसकी पुष्टि कंपनी की तरफ से किया जा चुका है। भारत में यह मारुति की पहली ऑल–इलेक्ट्रिक कार होगी। इसके नए स्पाई शॉट्स भारत–स्पेक ई विटारा में ADAS और डुअल स्क्रीन जैसे फीचर्स देखने के लिए मिले हैं। इसे 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। Maruti e Vitara मारुति की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश होने वाली है। इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया जाएगा, जो जनवरी 2025 के 17 तारीख से 22 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। इसमें पेश होने से पहले एक बार फिर ई-विटारा को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस दौरान इसके कुछ नए फीचर्स देखने के लिए मिले हैं।

टेस्टिंग मॉडल में क्या दिखा नया

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में डेब्यू करने से पहले दिखाई दी Maruti e Vitara के टेस्टिंग मॉडल में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) रडार देखने के लिए मिला है। यह भारत में मारुति की पहली पेशकश होगी, जिसमें यह सेफ्टी फीचर दिया जाएगा।

इसके साथ ही ई-विटारा के इंटीरियर्स की हल्की झलक देखने के लिए मिली है। जिसके मुताबिक, इसमें सिंगल स्क्रीन सेटअप और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिखाई दिया है, जैसा इसके ग्लोबल स्पेक वेरिएंट में देखने के लिए मिला है।

एक्सपेक्टेड फीचर्स

Maruti e Vitara में ऑटोमैटिक एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ई-विटारा को 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स से लैस किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे।

बैटरी पैक और रेंज

Maruti e Vitara में को भारत में 49 kWh और 61 kWh दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। इसे FWD और AWD दोनों में लाया जा सकता है। इसमें लगा हुआ 49 kWh बैटरी पैक 144 PS की पावर और 189 Nm का टॉर्क और 61 kWh बैटरी पैक 174 PS की पावर और 189 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा।

मारुति सुजुकी की तरफ से अभी तक इसके ड्राइविंग रेंज का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह करीब 550 किमी तक की रेंज दे सकती है।

कीमत और मुकाबला

भारत में Maruti e Vitara की एक्स-शोरूम कीमत 22 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG ZS EV, Tata Curve EV, Mahindra BE6, Mahindra XEV 9e और जल्द लॉन्च होने वाली Hyundai Creta EV से देखने के लिए मिलेगा।

मर्सिडीज G 580 भारत में 9 जनवरी को होगी लॉन्च; 30 मिनट में 10-80% तक चार्ज, 470 km से ज्यादा की मिलेगी रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

Mercedes G 580 भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे भारत में 9 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी पेश किया जाएगा। यह महज 30 मिनट में 10 प्रतिशत से लेकर 80 फीसद तक चार्ज हो जाती है। वहीं इसे फुल चार्ज करने पर 470 किमी से ज्यादा का रेंज मिलेगा।

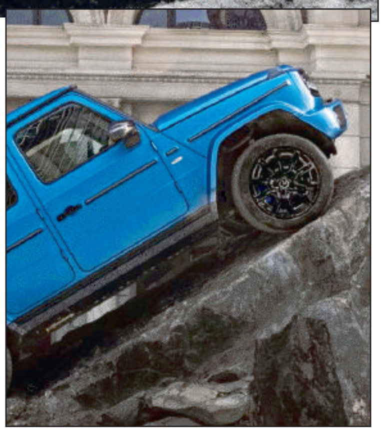

नई दिल्ली। Mercedes-Benz साल 2025 के शुरुआत में ही भारत में अपनी सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Mercedes G 580 है। यह G-क्लास या G-वैगन SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसे ऑफ-रोड खूबियों के लिए जाना जाता है। G 580 को भारत में 9 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं कि Mercedes G 580 भारत में किन खूबियों के साथ लॉन्च हो सकती है।

Mercedes G 580: एक्सटीरियर डिजाइन

मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक जी-क्लास एसयूवी के डिजाइन को ICE की तरह काफी हद तक सामान रखा गया है, लेकिन ईवी के रूप में अलग दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें लैडर-फ्रेम चेसिस देखने के लिए मिलेगा। इसमें ब्लैक फिनिशिंग के साथ एक क्लोज ग्रिल, गोल एलईडी हेडलाइट और सामने की तरफ डीआरएल यूनिट देखने के लिए मिलेंगे। इसमें ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पीछे की तरफ ऑप्शनल स्टोरेज बॉक्स भी दिया जा सकता है, जो स्पेयर व्हील केस के आकार का होगा।

इंटीरियर डिजाइन

इसका इंटीरियर इसके ICE मॉडल की तरह ही हो सकता है। इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। इसमें 12.3 इंच की स्क्रीन पर MBUX सिस्टम दिया जा सकता है, जो Apple CarPlay और Android Auto मिलेगा। इसमें कनेक्टेड ऐप के ज़रिए स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। इसके अलावा, G 580 को वायरलेस चार्जिंग, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, पीछे के यात्रियों के लिए मनोरंजन स्क्रीन, ADAS तकनीक के साथ-साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स से लैस किया जा सकता है।

बैटरी और रेंज

इलेक्ट्रिक G-क्लास SUV में 116 kWh का बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा। जिसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद करीब 470 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। Mercedes की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी यह एसयूवी करीब 30 मिनट में 0 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।

परफॉर्मेंस

मर्सिडीज इलेक्ट्रिक SUV में चार इलेक्ट्रिक मोटर देखने के लिए मिलेगा। हर इलेक्ट्रिक मोटर 579 bhp की पावर और 1,164 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी यह इलेक्ट्रिक SUV महज 5 सेकंड में 0 से लेकर 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है।

1 लाख की डॉउन पेमेंट में मारुति ऑल्टो K10 का CNG वेरिएंट लाएं घर, हर महीने इतनी देनी होगी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

कार फाइनेंस प्लान मारुति की तरफ से भारतीय बाजार में हैचबेक कार सेगमेंट में मारुति ऑल्टो K10 को पेश किया जाता है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसे एक लाख रुपये देकर LXI S-CNG या VXI S-CNG वेरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी।

नई दिल्ली। अगर आप Maruti Alto K10 को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको इसकी कीमत खासियत के साथ ही LXI S-CNG और VXI S-CNG मॉडल के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए कितना लोन लेना और इसके लिए हर महीने की किस्त यानी EMI कितनी जमा करनी पड़ेगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Maruti Alto K10 LXI S-CNG के लिए कितनी देनी पड़ेगी EMI

LXI S-CNG वेरिएंट सीएनजी का बेस वेरिएंट है। कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि यह एक किलो सीएनजी में 33 किमी तक का रेंज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,73,500 रुपये और ऑन-रोड कीमत 6,24,438 रुपये (नई दिल्ली) है। अगर आप Alto K10 के इस मॉडल को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुल 5,24,438 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। अगर यह लोन आप सात साल के लिए 9.8 प्रतिशत के इंट्रेस्ट रेट पर मिलता है। ऐसे में आपको हर महीने 8,652 रुपये EMI के रूप में बैंक या फाइनेंस कंपनी को देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको इस सात वर्षों में 2,02,346 रुपये इंट्रेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। ऐसे में आपको Maruti Alto K10 LXI S-CNG के लिए कुल 7,26,784 रुपये खर्च करना पड़ेगा।

Maruti Alto K10 VXI S-CNG के लिए कितनी देनी पड़ेगी EMI

VXI S-CNG वेरिएंट सीएनजी मॉडल का टॉप वेरिएंट है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,96,000 रुपये और ऑन-रोड कीमत 6,48,626 रुपये है। अगर आप Alto K10 के इस वेरिएंट को एक लाख रुपये के डाउन पेमेंट पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए कुल 5,48,626 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। अगर यह लोन 7 साल के लिए 9.8 प्रतिशत के इंट्रेस्ट रेट पर मिलता है तो आपको हर महीने 9,051 रुपये EMI के रूप में देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको इन सात वर्षों में कुल 2,11,679 रुपये इंट्रेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। इस तरह से आपको Maruti Alto K10 VXI S-CNG वेरिएंट कुल 7,60,305 रुपये में पड़ेगी।

Maruti Alto K10 के फीचर्स

कीमत- Alto K10 3.99 लाख रुपये से लेकर 5.96 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत में आती है।

वेरिएंट- Std, LXi, VXi और VXi Plus। वहीं, सीएनजी वेरिएंट LXI S-CNG और VXI S-CNG है।

कलर ऑप्शन- मैटेलिक सिज़लिंग रेड, मैटेलिक सिल्की सिल्वर, मैटेलिक ग्रेनाइट ग्रे, मैटेलिक स्पीडी ब्लू, प्रीमियम अर्थ गोल्ड, पर्ल मिडनाइट ब्लैक और सॉलिड व्हाइट है।

इंजन- Alto K10 में 1-लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 67 PS की पावर और 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT से जोड़ा गया है।

माइलेज- मारुति सुजुकी की तरफ से दावा किया जाता है कि Alto K10 एक लीटर पेट्रोल में 24.39 किलोमीटर तक का माइलेज और एक किलो CNG में 33.40 किलोमीटर तक का माइलेज देती है।

फीचर्स- Alto K10 में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्सिंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स से लैस किया गया है।

अपने आप बढ़ जाएगा बाइक का माइलेज, बस फॉलो करें 5 टिप्स

परिवहन विशेष न्यूज

हर बाइक राइडर चाहता है कि इसकी मोटरसाइकिल हमेशा अच्छा माइलेज दें। इसके लिए वह तरह–तरह के उपाय भी अपनाते हैं। हम यहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करने पर आपकी बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा होने के साथ ही माइलेज भी बेहतर होगा। आइए जानते हैं कि मोटरसाइकिल का माइलेज बढ़ाने के तरीकों के बारे में।

नई दिल्ली। भारत में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। जिसकी वजह से मोटरसाइकिल से अच्छा माइलेज हासिल करना प्राथमिकता बन गई है। हम अपनी बाइक चलाने का आनंद लेते हैं, लेकिन वह उम्मीद के अनुसार माइलेज नहीं देती है। जिसकी वजह से राइडर कई बार निराश भी होते हैं। खासकर वह लोग जो रोजाना 25-30 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल का माइलेज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

1. कार्बरेटर को रीट्यून करें

कार्बरेटर को रीट्यून करने से आपकी बाइक का माइलेज बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। अगर आपकी बाइक का माइलेज कम है तो उसके कार्बोरेटर सेटिंग्स को जरूर चेक करें। अगर उसमें किसी तरह की खराब दिखाई देता है तो मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक श्राप से रीट्यून करें। इससे इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होने के साथ ही माइलेज भी बेहतर हो सकता है।

2. फालतू में फ्यूल बर्बाद न करें

अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पर 20 सेकंड से ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़े तो बाइक के इंजन को बंद कर दें। अगर आप इंजन को ऑन करके रखते हैं तो फ्यूल बर्बाद होता है। खासतौर पर शहरों में जहां पर रूक-रूक कर चलता है।

3. टायर का प्रेशर चेक करें

बाइक के टायर प्रेशर को हमेशा सही रखना चाहिए। बाइक निर्माता कंपनी के द्वारा बताए गए एयर प्रेशर को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। वहीं, अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर टायर में एयर प्रेशर को जरूर चेक करें।

4. मोटरसाइकिल को साफ रखें

आपको अपनी बाइक को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। इस दौरान बाइक के चलने वाले सभी पार्ट को लुब्रिकेट जरूर करें। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और परफॉर्मेंस बना रहता है। जिसकी वजह से आपकी बाइक अच्छा माइलेज देती है।

5. मॉडिफिकेशन से बचें

जब भी बाइक को डिजाइन किया जाता है उसे बनाने वाले इंजीनियर उसके एयरोडायनामिक दक्षता का ध्यान रखते हैं। यह बाइक की परफॉर्मेंस को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसलिए बाइक पर मॉडिफिकेशन करवाने से बचना चाहिए। इससे न केवल एयरोडायनामिक प्रभावित होता है बल्कि माइलेज पर भी असर पड़ता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

आपको तेज गति से बाइक चलाने से बचना चाहिए।

बाइक को अचानक ब्रेक लगाकर नहीं रोकना चाहिए।

बाइक के गियर का सही से इस्तेमाल करें।

बाइक की नियमित रूप से सर्विस करवाएं।

3.30 लाख में कावासाकी लाई ऑफ-रोडिंग का नया किंग KLX 230! टूटी सड़क हो या चिकनी रोड हर जगह चलेगी स्मूद

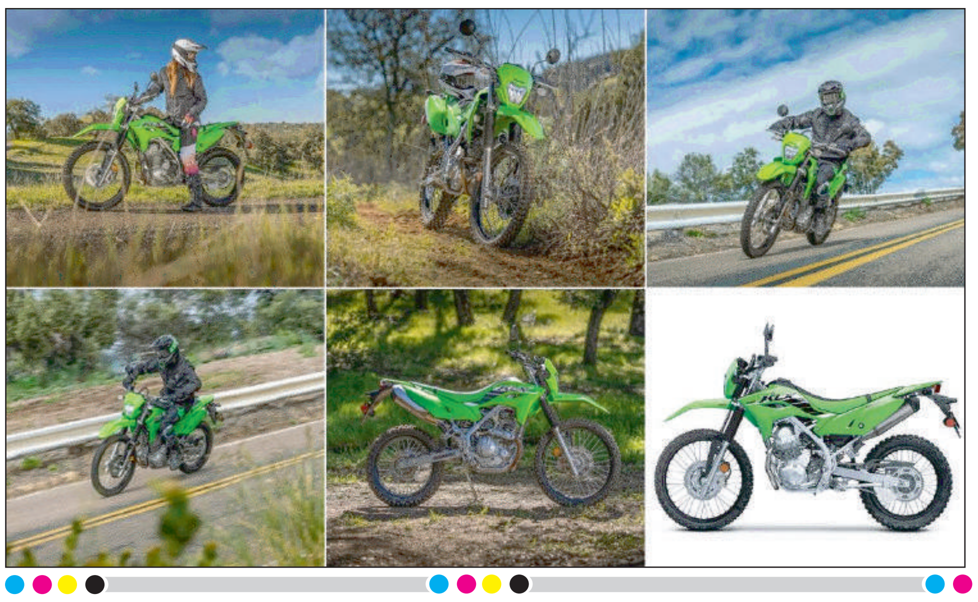

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी बाइक निर्माता कंपनी कावासाकी ने Kawasaki KLX 230 को लॉन्च किया है। इस बाइक को ऑफ–रोड और ऑन–रोड दोनों के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें हेक्सागोनल हेडलाइट समेत डिजिटल LCD डिस्प्ले और स्विचेबल डुअल–चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि Kawasaki KLX 230 को भारत में किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

नई दिल्ली। जापानी बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki अपनी हाई पिकअप बाइक के लिए जाना जाता है। कावासाकी की लाइट वेट मोटरसाइकिल दमदार कलर ऑप्शन और पावरफुल पावरट्रेन के साथ आती है। कंपनी ने अपनी एक लाइट वेट बाइक Kawasaki KLX 230 को भारत में लॉन्च किया है। इस रेसर लुक बाइक रियर सीट पर बैक रेस्ट और सिंपल हैंडलबाइक और रियर व्यू के साथ आई है। आइए जानते हैं कि Kawasaki KLX 230 किन फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च की गई है।

डिजाइन और लुक

Kawasaki KLX 230 को स्लीक और शानदार डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें हेक्सागोनल हेडलाइट दी गई है। इसके चारों तरफ प्लास्टिक काउल दिए गए हैं। इसमें लंबा फ्रंट फेंडर दिया गया है, जिसकी वजह से इसे ऑफ-रोडिंग ड्राइव करने में राइडर को काफी आराम मिलता है। इसमें स्लिम सीट और ऊपर उठे हुए एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में डिजिटल LCD डिस्प्ले और स्विचेबल डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

Kawasaki KLX 230 में 233 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 18.1bhp की पावर और 18.3Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इससे अगर आप लंबा सफर करते हैं तो इसके लिए फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर मोनोशॉक काफी बेहतरीन दिया गया है, जिससे काफी स्मूद हैंडलिंग मिलती है।

यह भी पढ़ें- Kawasaki की मोटरसाइकिलों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, Ninja 650 पर 45,000 रुपये की छूट

ब्रेकिंग सिस्टम

कावासाकी KLX 230 में काफी बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, इसमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसमें आगे की तरफ 21-इंच और पीछे की तरफ 18-इंच रियर स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इसमें रोड-बायस्ड टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों के लिए काफी बेहतरीन है।

कीमत और मुकाबला

Kawasaki KLX 230 को भारत में 3.30 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे अगले महीने होने जा रही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में भी पेश किया जाएगा। वहीं, उसके बाद से इसकी डिलिवरी भी शुरू किया जा सकता है। भारतीय बाजार में कावासाकी की यह मोटरसाइकिल Hero Xpulse 200 4V को टक्कर देते हुए दिखाई देगी।

फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण, चलना हुआ मुश्किल

आजकल हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स ने व्यस्त बाज़ार के पास नो–वेंडिंग ज़ोन में स्टॉल लगा रखे हैं। इनके लिए नो–वेंडिंग ज़ोन की स्थापना सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा सकती है। हालाँकि, इनमें से कई विक्रेता अपने परिवार, जिसमें बुज़ुर्ग माता–पिता और स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल हैं, को पालने के लिए पूरी तरह से अपनी कमाई पर निर्भर हैं। हालांकि इनके लिए स्थानीय दुकानदारों के संघ शिकायतें भी दर्ज करवाते हैं कि विक्रेता भीड़भाड़ पैदा कर रहे हैं और उनके व्यवसाय को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन विक्रेताओं की आर्थिक कमज़ोरी को समझते हुए इसके लिए मानवीय समाधान ज़रूरी है। ऐसे मामले एक मध्यम आकार के शहर में शहरी शासन और सामाजिक समानता के बीच संघर्ष को उजागर करता है। शहरों के फुटपाथों और सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास तो कई बार होते हैं लेकिन इन प्रयासों में कभी भी गंभीरता नहीं रही है। इसका नतीजा यह रहा कि कुछ दिनों तक चलने के बाद यह अभियान ठप हो जाते हैं और स्थिति जस की तस हो जाती है। इससे लोग परेशान रहते हैं।

प्रियंका सौरभ

मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, गलियों में दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों की ओर से किया गया अतिक्रमण दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। परिणामस्वरूप शहर के बाजारों में वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्ट्रीट वेंडर्स, जो अपने जीवनयापन के लिए अपने व्यापार पर निर्भर हैं, ने हर एक व्यस्त बाज़ार के पास निर्दिष्ट नो-वेंडिंग ज़ोन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और स्थानीय दुकानदारों की ओर से शिकायतें आ रही हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं और विक्रेताओं की आर्थिक कमज़ोरी के बीच संतुलन बनाना एक नैतिक और प्रशासनिक चुनौती है। स्ट्रीट वेंडर दुनिया भर की शहरी अर्थव्यवस्थाओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं। भले ही स्ट्रीट वेंडर्स को अनौपचारिक माना जाता है, लेकिन वे शहरी अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। इस 21वीं सदी में ज़्यादातर लोग स्ट्रीट वेंडर हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था निगरानी अध्ययन ने उन तरीकों का खुलासा किया है, जिनसे स्ट्रीट वेंडर अपने समुदायों को मज़बूत बना रहे हैं: स्ट्रीट वेंडिंग रोज़गार सृजन, उत्पादन और आय सर्जन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यस्थल पर जनता, पुलिस कर्मियों, राजनेताओं और स्थानीय उपद्रवियों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जीवनयापन के लिए वेंडिंग पर निर्भर हैं। विक्रेताओं द्वारा की गई प्रतिस्पर्धा और भीड़भाड़ के कारण नुक़सान का दावा करना उनकी मजबूरी है। व्यस्त बाज़ार में यातायात का सुचारू प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता भी ज़रूरी है। विक्रेताओं के लिए मानवीय और टिकाऊ समाधान की वकालत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने का कार्य है। स्ट्रीट वेंडर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए वेंडिंग पर निर्भर हैं। हालाँकि, उनकी उपस्थिति से भीड़भाड़ होती है और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। ट्रैफ़िक प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखते हुए उनकी आजीविका की रक्षा के लिए एक संतुलन की आवश्यकता है। दुकानदार विक्रेताओं को उनकी कम लागत और अनौपचारिक संचालन के कारण अनुचित प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। हालाँकि, विक्रेता अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से सम्बंधित होते हैं। समाधान में समानता की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानदारों के हितों को अनुचित रूप से नुक़सान न पहुँचाया जाए। जबकि आर्थिक विकास एक संपन्न शहर के लिए महत्त्वपूर्ण है, सामाजिक कल्याण नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर जैसे कमज़ोर समूहों को असंगत कठिनाई का सामना न करना पड़े। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नीतियों में आर्थिक विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों के कल्याण दोनों को एकीकृत किया जाना चाहिए। कई विक्रेता अपने परिवारों के लिए कमाने वाले होते हैं, जो बुज़ुर्ग आश्रितों और स्कूल जाने वाले बच्चों का भरण-पोषण करते हैं। बिना किसी विकल्प के उन्हें विस्थापित करने से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, जिससे निर्णय लेने में करुणा आवश्यक हो जाती है। निर्णय पारदर्शी और समावेशी होने चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान हो। किसी भी समूह को बाहर रखने से अशांति फैल सकती है और प्रशासन की निष्पक्ष रूप से शासन करने की क्षमता पर भरोसा कम हो सकता है।

शहरों की आबादी समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और रोजगार के लिए लोगों का बाहर आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है लेकिन शहरों में इन समस्याओं का निदान करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो पहल होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद शहरों में पार्किंग और रेडी-फड़ी जोन बनाए जाने की बात सामने आती है, लेकिन वह आज तक ज़मीन पर दिखाई नहीं देती है। लिहाजा ऐसी समस्याओं का बना रहना स्वाभाविक है। इसके स्थायी समाधान के लिए नो-वेंडिंग ज़ोन में समय-आधारित वेंडिंग शेड्यूल लागू करें ताकि ट्रैफ़िक प्रवाह को बनाए रखते हुए गैर-पीक घंटों के दौरान विक्रेताओं को अनुमति दी जा सके। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पीक घंटों के दौरान निगरानी बढ़ाएँ। स्वच्छता और पीने के पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक निर्दिष्ट वेंडिंग ज़ोन विकसित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि विक्रेताओं के पास काम करने के लिए एक स्थायी स्थान हो। विक्रेताओं की संख्या को विनियमित करने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करें। यह दृष्टिकोण विक्रेताओं और दुकानदारों की तत्काल ज़रूरतों को सम्बोधित करता है और साथ ही भविष्य के लिए एक स्थायी ढाँचा तैयार करता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक निष्पक्षता और दयालु शासन को संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों को सुना और समर्थन दिया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदारों और जनता की ज़रूरतों को सम्बोधित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। पीएम स्वनिधि योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 उनके अधिकारों की रक्षा करता है। भविष्य में, कौशल विकास की पेशकश, अधिक वेंडिंग जोन बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से विक्रेताओं को शहर की अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने और एकीकृत होने में मदद मिलेगी।

'हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी... न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।'

26 दिसंबर 2024 को आर्थिक सुधारों के पुरोधा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री (14 वें) डॉ.मनमोहन सिंह का हमारे बीच से 92 वर्ष की उम्र में अवसान हो गया। सभी जानते हैं कि डॉ सिंह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने नीतियों और नेतृत्व से भारत को आर्थिक और वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सच तो यह है कि उनके आर्थिक सुधारों को पूरी दुनिया ने लोहा माना है।सच तो यह है वे देश में उदारीकरण लेकर आए।कहना ग़लत नहीं होगा कि वे सादगी, विनम्रता और विद्वता की मूरत थे। अविभाजित भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को जन्मे डॉ सिंह ने कैमब्रिज और आक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। श्री गुरमुख सिंह और श्रीमती अमृत कौर के घर जन्मे सिंह ने 1948 में पंजाब में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। कैंब्रिज से उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नाफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में 'डी.फिल' की उपाधि प्राप्त की।उन्होंने योजना आयोग उपाध्यक्ष (अब नीति आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गर्वनर, और आर्थिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी थी। बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत 2006-2007 में भारत ने 10.08% की वृद्धि दर दर्ज की थी। यह 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक जीडीपी थी। उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर 2006-2007 में 10.08% थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह ने जुलाई, 1991 के बजट में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, 'पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना चाहिए, यह एक ऐसा ही एक विचार है।' वे वित्त मंत्रालय में सचिव, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के वित्त मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने अनेक आर्थिक सुधार किए। पाठकों को बताता चलूं कि वर्ष 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई तथा 1971 में, डॉ. सिंह वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार तथा वर्ष 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। यदि हम यहां उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो डॉ.मनमोहन सिंह 1991 से भारत के संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 के बीच विपक्ष के नेता थे। उल्लेखनीय है कि वे पहली बार 1991 में राज्य सभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने उच्च सदन में पांच बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।पाठक जानते हैं कि वे वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने 22 मई 2004 को प्रथम बार और 22 मई 2009 को दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। उल्लेखनीय है कि वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे।वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। अपने दस साल के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने देश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई), सूचना का अधिकार (आरटीआई, वर्ष 2005), विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना मनरेगा योजना (वर्ष 2005) समेत तमाम कई बड़े फैसले लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। उल्लेखनीय है कि 'आधार योजना' भी उनके ही कार्यकाल में शुरू की गई थी। कहना ग़लत नहीं होगा कि आधार योजना से भारतीयों को नव पहचान मिली और इससे आमजन की विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान और सरल हो गई। साथ ही कई पहचान पत्रों की जगह इस एक पहचान पत्र आधार कार्ड ने लोगों का जीवन आसान किया। इतना ही नहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) यानी कि लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली भी उनके ही कार्यकाल की देन है जिससे भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगी और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौता भी डॉ. सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। यहां यह भी गौरतलब है कि वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकते हुए उसे उबारा था। पाठकों को बताता चलूं कि उन्होंने 'भारत के निर्यात रुझान और स्व-संचालित विकास की संभावनाएं' शीर्षक से किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की आलोचना की थी। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी के रूप में तथा यूएनसीटीएडी (अंकटाड) यानी कि (व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) में 1966-1969 तक सचिवालय में भी काम किया। 1969 से 1971 तक, सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी रहे। पुरस्कारों और सम्मानों की यदि बात करें तो उन्हें 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण, वर्ष 1995 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष 1993 और 1994 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार, वर्ष 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैमब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैमब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार (1955) प्रदान किये गए थे। इतना ही नहीं उन्हें कैमब्रिज और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त हुईं थीं। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। गौरतलब है कि साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (वर्ष 1993) और वर्ष 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि मनमोहन सिंह की छवि बेशक बहुत ही कम बोलने वाले और अधिकतर शांत रहने वाले व्यक्तियों में की जाती रही है, लेकिन जब भी वे बोलते थे, वो सुर्खियां बन जाती थीं। मसलन,27 अगस्त 2012 को संसद में उन्होंने यह कहा था कि 'हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी है...न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।' इतना ही नहीं, 23 मार्च 2011 को नेता विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज के एक तंज पर जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा था- 'माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख मेरा इंतजार तो देख।' बहरहाल, अंत में यही कहूंगा कि भले ही आज डॉ सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे देश-दुनिया के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक हैं। आर्थिक नीतियों के संबंध में उन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी है। उनको शत-शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।

सुनील कुमार महला

मुफ्त की चुनावी घोषणाएं बिगाड़ रहीं हैं आर्थिक सेहत

योगेंद्र योगी

चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली आप अकेली पार्टी नहीं हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों में खैरात बांटने की होड़ लग जाती है। इसका एकमात्र मकसद चुनाव जीतना है। इसके नुकसान–फायदों की राजनीतिक दलों का परवाह नहीं हैं।

दिल्ली चुनाव को अभी एक महीने से ज्यादा का समय बाकी है। उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आएंगे। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद इसको बदलकर 2100 रुपए करेंगे। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली आप अकेली पार्टी नहीं हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों में खैरात बांटने की होड़ लग जाती है। इसका एकमात्र मकसद चुनाव जीतना है। इसके नुकसान-फायदों की राजनीतिक दलों का परवाह नहीं हैं। यह अलग बात है कि चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो खरबूजे को ही है। मसलन फ्री का माल लेने वाले को भी आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी न किसी रूप में टैक्स का बोझ उन पर भी पड़ता है। फ्री की योजनाओं का फायदा उठाने वाले भी इससे बढने वाली महंगाई की मार से बच नहीं सकते।

इससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और तीन साल के लिए फ्री इंटरनेट का वायदा किया था। गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत सवा करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये जमा कराए। कांग्रेस ने वादा किया था कि उसकी सरकार आई तो हजार नहीं बल्कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक-एक स्कूटी देने का भी ऐलान किया था। चुनावी रेवड़ी बांटना का कल्चर शुरु से ही विवादों से घिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक विशेषज्ञ, चुनाव आयोग और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक इस पर चिंता जता चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल व्यापक देशहित से जुड़े ऐसे मुद्दों का समाधान तलाशना तो दूर बल्कि चर्चा तक करना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और अन्य मुफ्त योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर लोगों को ₹फ्री की रेवड़ी₹ कब तक बांटी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन देना समय की जरूरत थी, लेकिन अब रोजगार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, ₹तो मतलब सिर्फ टैक्सपेयर्स ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है। यह स्थिति गंभीर विचार का विषय है।₹ वर्ष २०२२ में श्रीलंका का आर्थिक संकट सामने आया तो इसने दुनियाभर की सरकारों को चेता दिया। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि श्रीलंका से सबक लेते हुए हमें मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बहुत मजबूत है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मोदी ने कहा था कि हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।

भारत में ऐसी लुभावनी पर आर्थिक तौर पर घातक चुनावी वायदों की शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। वर्ष 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी अन्नाद्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कम्प्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50 हजार रुपये और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का वादा भी किया।

नतीजे आए तो अन्नाद्रमुक की सरकार बन गई। 2006 के चुनावी वादे पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिला देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह-मशविरा कर एक आचार संहिता बनाए। इसके बाद 2015 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी भी की, लेकिन उसके बावजूद चुनावों में फ्रीबीज का ऐलान होता ही रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कहा था, ऐसी योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स भागीदारी कम हो तो वो फ्रीबीज होती हैं। वर्ष 2022 पिछले साल आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। स्टेट फाइनेंसेसः अ रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन पांच राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल थे। चुनावी वादों के कारण बढ़ रही मुद्रास्फीती और महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। राजनीतिक दलों का इससे सरोकार नहीं है। सत्ता में आने के बाद सरकारें फ्री देने के वादे पूरा करने के लिए टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही हैं। होना तो यह चाहिए कि कोई राजनीतिक दल जब ऐसी मुफ्त की चुनावी घोषणाओं का ऐलान करे तो साथ ही यह भी बताए कि इसके लिए धन का इंतजाम कैसे किया जाएगा।

एक्सीडेंटल राजनेता, क्रांतिकारी अर्थशास्त्री

उमेश चतुर्वेदी

मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप ही याद किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को राजनेता भी होना चाहिए। मनमोहन आधुनिक और प्रचलित अर्थों में राजनेता नहीं थे। उनके ही मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा है।

साल 1999 के आम चुनावों में दिल्ली की सात में छह सीटों पर तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। दक्षिण दिल्ली की इकलौती ऐसी सीट रही, जहां बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा को जीत मिली थी। मल्होत्रा के सामने जिन्हें हार मिली थी, वे राजनेता मनमोहन सिंह थे। उन दिनों मैं दैनिक भास्कर के दिल्ली ब्यूरो में काम करता था। अखबारी रिपोर्टिंग की एक रवायत है। वह विजेताओं को ही खोजती है और उनकी ही बात करती है। लेकिन हमारे तत्कालीन ब्यूरो चीफ और दिग्गज पत्रकार शरद द्विवेदी ने मुझे सफदरजंग रोड भेज दिया, जहां मनमोहन सिंह बतौर राज्यसभा सांसद रह रहे थे। शरद द्विवेदी का तर्क था कि मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले राजनेता हैं। उनके घर का माहौल देखना चाहिए और उस पर स्टोरी लिखनी चाहिए।

मैं जब मनमोहन सिंह के घर पहुंचा तो वहां करीब साठ-सत्तर कार्यकर्ता मौजूद थे। बंगले में एक तरह से उदासी छायी थी। एक ड्रम में रसना घोल रखी गई थी और आने वाले लोगों को पिलाई जा रही थी। वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, सिवा राजस्थान के रामनिवास मिर्धा के। मिर्धा भी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। और तो और, वहां पत्रकार भी नहीं थे। मेरे पहुंचने के बाद बंगले में सिर्फ एक और पत्रकार आए। इस बीच साधारण से सफेद कुर्ता-पाजामा और नीली पगड़ी में मनमोहन सिंह मेरी तरफ मुखातिब हुए। उन्हें मैंने बतौर पत्रकार परिचय दिया तो उन्होंने कांपते हाथों से हाथ मिलाया और फिर उसी तरह तकरीबन कांपते हुए रसना का गिलास मुझे थमा दिया। उस वक्त मैंने बचकाना सा सवाल पूछ लिया था, क्या सोच रहे हैं?

मनमोहन सिंह को उसके बाद राज्यसभा और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खूब देखा। वे कभी पढ़ते हुए दिखते तो कभी चुपचाप बैठे हुए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के इंडिया शाइनिंग अभियान को धत्ता बताते हुए कांग्रेस की अगुआई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने केंद्रीय सत्ता का दावेदार बन गया। तब शायद ही किसी ने सोचा था कि मनमोहन सिंह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त माना यह जा रहा था कि अगर किसी वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी तो प्रणब मुखर्जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी की बजाय

मनमोहन सिंह पर भरोसा किया।

1991 में जब नरसिंह राव ने केंद्र की सत्ता संभाली, तब देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे विदेशी विनिमय के लिए अपना 67 टन सोना ब्रिटेन में गिरवी रखकर उसके एवज में 2.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा था। ऐसे माहौल में नई सरकार के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती थी। लेकिन नरसिंह राव ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण के साथ ही आर्थिक सुधारों की शुरूआत की। 1991 के चुनावों के बाद बनी नई सरकार ने 25 जुलाई 1991 को नया बजट पेश किया। उसी बजट को पेश करते हुए बतौर वित्त मंत्री देश को नई आर्थिक राह पर लेकर चल पड़े। उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार के साथ देश आर्थिक मोर्चों को फतह करते हुए आगे बढ़ चला। इस राह पर देश आज कितना आगे बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश का आज आर्थिक नक्शा बदला हुआ नजर आता है तो उसकी बड़ी वजह मनमोहन सिंह की रखी हुई बुनियाद ही है।

मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप ही याद किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को राजनेता भी होना चाहिए। मनमोहन आधुनिक और प्रचलित अर्थों में राजनेता नहीं थे। उनके ही मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा है। मनमोहन सिंह पर आरोप लगा कि वे कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार को सलाह देने के लिए सोनिया गांधी की अगुआई में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सलाहकार कम, आदेश देने वाली संस्था है। उनकी ही सरकार ने तीन साल की सजा पाने वाले राजनेताओं की संसद और विधानमंडल की सदस्यता खत्म होने को रोकने वाला अध्यादेश पारित किया था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ कर एक तरह से उस अध्यादेश को प्रभावहीन कर दिया था।

मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, दस साल देश के प्रधानमंत्री रहे। पहले कार्यकाल में तो नहीं, लेकिन 2009 से 2014 के कार्यकाल में उनकी सरकार और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। बेशक प्रधानमंत्री के रूप में उनके चरित्र और दामन पर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन उनकी चुप्पी देश को खलती रही। इसलिए उन्हें मौनमोहन तक कहा जाने लगा था।

बिल्कुल मामूली परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र की ऊंची शिक्षा हासिल की। कैंब्रिज में अर्थशास्त्र की ऊंची शिक्षा ली, दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में अर्थशास्त्री रहे, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग में रहे, वित्त मंत्री रहते हुए इतिहास ही रचा।

मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री कुछ बयान विवादास्पद भी रहे। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उनका एक और बयान था कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने जब कृतज्ञ भाव से अंग्रेजों की ओर से भारत को बड़ी देन अंग्रेजी को बताया था, तब भी उन पर सवाल उठे थे।

मनमोहन सिंह सरलता और सादगी की मिसाल थे। यह सादगी उनकी ताजिंदगी पहचान रही। वे सहज भी रहे। प्रणब मुखर्जी उनके राजनीतिक बॉस रह चुके थे। बाद के दिनों में उनके मंत्रिमंडल में मुखर्जी बतौर वित्त मंत्री शामिल थे। तब भी मनमोहन उन्हें पहले की तरह सर ही कहा करते थे। जिस पर मुखर्जी ने प्रतिवाद किया था और उन्हें सर कहने से रोक दिया था। इसका खुलासा खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने एक साक्षात्कार में किया था।

हर व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं। मनमोहन भी इस मानवीय व्यवहार के अपवाद नहीं थे। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी सादगी और सरलता तो याद रहेगी, देश के आर्थिक भाग्य को बदलने वाले के रूप में उनकी छाप सदा अमिट रहेगी। भारत इसके लिए उनका शुक्रगुजार ही नहीं, ऋणी भी रहेगा।

2025 में क्या पूरा होगा घर खरीदने का सपना, प्रॉपर्टी प्राइसेस में कमी आएगी या उछाल?

परिवहन विशेष न्यूज

रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए साल 2024 कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। घर खरीदारों को भी EMI के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत नहीं मिली क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। हालांकि 2025 से रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को काफी उम्मीदें हैं। आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है जिससे ब्याज दरें सस्ती हो सकती हैं।

नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साल 2024 काफी मिला-जुला रहा। कई सेगमेंट में बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला, तो कुछ काफी सुस्त भी रहे। आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई ने पूरे साल केंद्रीय बैंक को राहत की सांस नहीं लेने दी। इससे बाकी लोन के साथ होम लोन की EMI भी ऊंची बनी रही, जिसका घरों की बिक्री पर असर पड़ा। आइए जानते हैं कि 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्या घरों की बिक्री बढ़ेगी। साथ ही, होम लोन की ब्याज दरों में कमी होगी या इजाफा?

2024 में कैसा रहा रियल एस्टेट सेक्टर प्रदर्शन

रियल एस्टेट मार्केट के जानकारों का दावा है कि 2023 के मुकाबले 2024 में बाजार कुछ सुस्त रहा। प्रॉपइक्विटी के फाउंडर और सीईओ समीर जसूजा का कहना है, '2024 के दौरान रिहायशी रियल एस्टेट मार्केट में मांग और आपूर्ति में गिरावट आई है, जो 2023 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर गई थी। हालांकि Supply-Absorption Ratio स्थिर बना हुआ है। यह इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है।' जसूजा ने यह भी कहा कि टियर 2 मार्केट्स में प्रॉपर्टी की मांग में कुछ उछाल देखने को मिला। ये भविष्य में बड़े बाजार बन सकते हैं।

गुरुग्राम स्थित प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म इन्फ्रा मंत्रा के डायरेक्टर और को-फाउंडर गर्वित तिवारी का भी यही मानना है। तिवारी का कहना है, 'अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिख रहे हैं। जीडीपी गिरने, मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साल के दौरान घर खरीदारों और निवेशकों में ठहराव देखा गया। अप्रैल-सितम्बर के दौरान चुनाव और मानसून को भी इसका कारण माना जा सकता है। इसके चलते घरों की बिक्री 2023 के रिकॉर्ड स्तर से मामूली कम हुई। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत बना हुआ है।'

लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में दिखी अच्छी डिमांड

लग्जरी हाउसिंग मार्केट ने 2024 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरपर्सन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ₹2024 में रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आया। इसे बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और किफायती, मध्यम आय और लग्जरी सेगमेंट में बढ़ती मांग का समर्थन मिला। आवासीय मांग विशेष रूप से मजबूत रही है। लग्जरी मार्केट में गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी डिमांड देखी गई। वहां हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNWI) और NRI प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा लगा रहे हैं, जो बेहतरीन सुविधाओं से लैस ठिकाना चाहते हैं।'

अनंत राज लिमिटेड के सीईओ अमन सरीन का भी कहना है कि लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा, '2024 में आवास क्षेत्र में मजबूत गति देखी गई। इसमें लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट केंद्र में रहे। एमएमआर और गुरुग्राम-एनसीआर जैसे शहरों में 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली उच्च-स्तरीय संपत्तियों की मांग में उछाल देखा गया। इसकी वजह रहने के लिए प्रीमियम जगह की तलाश करने वाले संभावित खरीदारों की बढ़ती संख्या रही।'

2025 में रियल एस्टेट सेक्टर कैसा रहेगा

रियल इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि साल 2025 में इंडस्ट्री काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। खासकर, यह देखते आरबीआई फरवरी की एमपीसी से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है। बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा का कहना है, 'आरबीआई 2025 में कटौती कर सकता है, जिससे होम बायर्स के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है। इससे खासतौर पर पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा होगा, जो ऊंची EMI के चलते फिलहाल घर खरीदने में झिझक रहे हैं।'

अतुल मोंगा का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को बढ़ावा देने से शहरी हाउसिंग मार्केट में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। टैक्स में फायदा, ब्याज में सब्सिडी और बढ़ते फाइनेंशियल सपोर्ट से इस सेगमेंट में होम लोन की डिमांड भी बढ़ेगी।

अनंत राज लिमिटेड के अमन सरीन की भी कुछ इसी तरह की राय है। उनका कहना है कि साल 2025 में सभी आवास खंडों में मजबूत डिमांड बनी रहने के आसार हैं। इसकी वजह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्थिर ब्याज दर और बेहतर उपभोक्ता विश्वास रहेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी की एमपीसी में ब्याज दरों में कटौती होने की भी काफी संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर को इसका भी फायदा मिलेगा।

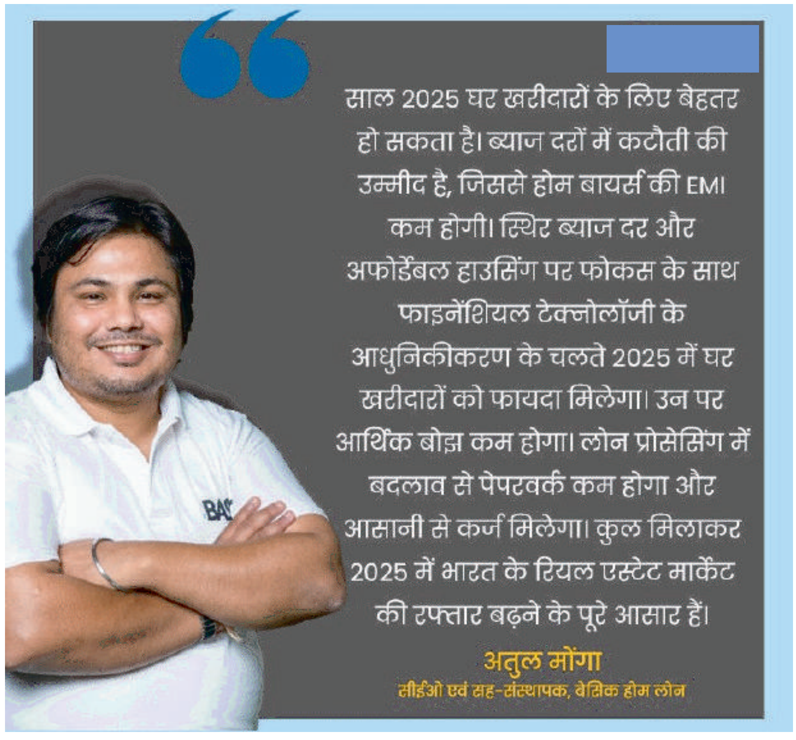

नई योजनाओं के लिए रेलवे अपनाएगा पीपीपी मॉडल, निजी निवेश से बढ़ेगा विकास

इशिका मुख्य रिपोर्टर

भारतीय रेलवे ने अपनी विकास योजनाओं में तेजी लाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाने की तैयारी कर ली है। इस मॉडल के तहत रेलवे नए प्रोजेक्ट्स में निजी कंपनियों को शामिल कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीपीपी मॉडल के जरिए सरकार रेलवे नेटवर्क के विस्तार, नई लाइनें बिछाने और मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। यह पहल रेलवे के 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकारी लक्ष्य में योगदान करेगी।

पीपीपी मॉडल की योजना

इस मॉडल के तहत निजी कंपनियां नई रेलवे परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव में निवेश करेंगी। बदले में उन्हें राजस्व साझेदारी, संचालन अधिकार और अन्य लाभ दिए जाएंगे। रेलवे की प्रमुख योजनाओं में हाई-स्पीड कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशन पुनर्विकास और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल हैं।

रेलवे ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने निजी कंपनियों और डेवलपर्स को आमंत्रित करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स की प्राथमिक सूची तैयार की है। इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, डिजाइन और निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

वर्तमान में भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2030 तक इसे और विस्तारित करने की योजना है। इस पहल से न केवल रेल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी अत्यधिक प्रभावी बनेगा।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, पीपीपी मॉडल से रेलवे को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि यह यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाएगा। रेलवे का लक्ष्य अधिक पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन सेवा प्रदान करना है।

भविष्य की योजनाएं

रेलवे बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि पीपीपी मॉडल के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ किया जाएगा। इससे रेलवे न केवल नई तकनीक अपनाएगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। यह मॉडल निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच सहयोग का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

मनरेगा से लेकर शिक्षा और सूचना के अधिकार तक, मनमोहन सिंह ने कैसे बदली भारत की तकदीर?

परिवहन विशेष न्यूज

डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके 10 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनीं जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। इनमें मनरेगा शिक्षा का अधिकार सूचना का अधिकार और आधार योजना शामिल हैं। आइए जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने इन योजनाओं को कैसे लागू किया और इनसे देश की सूरत कैसे बदली।

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की तरक्की की दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने बतौर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भारत को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले। उनकी आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 1991 के क्रांतिकारी बजट के बाद दो साल में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर हो गया। 1998 में यह 290 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

मनमोहन सिंह 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1991 में बतौर वित्त मंत्री जो आर्थिक सुधार किए थे, उसे आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं मनमोहन सिंह की अगुआई वाली सरकार के बड़े फैसलों के बारे में, जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदल दी।

रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

मनमोहन सिंह सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार का मौका मिला और उनके आर्थिक हालत सुधरे। इस योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की है। उसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोक-निर्माण कार्यक्रम करार दिया है। इससे देश की 15 फीसदी आबादी को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है।

शिक्षा का अधिकार

मनमोहन सिंह की सरकार 6 से 14 को शिक्षा का मौलिक अधिकार (RTE) दिया। इसे 4 अगस्त 2009 को संसद से पास किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 21a के तहत भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। इस योजना के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती है।

सूचना का अधिकार

राइट टु इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट देश की जनता को सरकारी अधिकारियों और संस्थानों से सूचना मांगने का हक देता है। इससे लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली। जवाबदेही को बढ़ावा मिला। यह एक्ट भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी कारगर साबित हुआ।

आधार योजना

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पहचान के लिए आधार कार्ड बनाने की शुरुआत हुई। उन्होंने 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया था। आधार योजना की तारीफ संयुक्त राष्ट्र तक भी कर चुका है। आधार की मदद से सरकार को कई योजनाओं का आर्थिक लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने में मदद मिली।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश के करीब 140 करोड़ लोगों में से लगभग दो तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसका मकसद है कि देश का कोई नागरिक भूखा न रहे। इसमें सरकार गरीब जनता क सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में बेहतर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ताकि लोगों खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें।

अमेरिका से न्यूक्लियर डील

अमेरिका से न्यूक्लियर डील प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की एक और बड़ी उपलब्धि है। खासकर, यह देखते हुए कि मनमोहन सिंह गठबंधन की सरकार चला रहे थे और इस समझौते से उनकी सरकार तक खतरे में आ गई थी। लेकिन, वह समझौते से पीछे नहीं हटे। उस डील के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। इस सौदे ने अमेरिका के साथ संबंधों को नया मोड़ दिया।

फ्लाइट के लिए 'लगेज रूल' में बदलाव, अब सिर्फ एक हैंड बैग ले जाने की इजाजत; जानें पूरी डिटेल

फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए एक खास नियम बदल गया है। अगर आपको इस नियम के बारे में नहीं पता रहेगा तो एयरपोर्ट और फ्लाइट में आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है। अब विमानन कंपनियां यात्रियों को सिर्फ एक ही हैंड बैग फ्लाइट में ले जाने की इजाजत देंगी।

नई दिल्ली। अगर आप भी नए साल की छुट्टियों के लिए हवाई सफर का प्लान बना रहे हैं, तो आपको नए लगेज नियमों के बारे में जानना जरूरी है। नहीं तो आपको एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट में परेशानी हो सकती है। दरअसल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि नए नियम क्या है और उनका आप क्या असर पड़ेगा?

नई हैंड बैग पॉलिसी में क्या है?

फ्लाइट में लगेज ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अब यात्रियों को फ्लाइट के अंदर सिर्फ एक ही हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की इजाजत होगी। यह नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट, दोनों पर लागू होंगी। एक बैग के अतिरिक्त जो भी बैग होंगे, उनका चेक-इन कराना जरूरी है।

एयर इंडिया का हैंड बैग के लिए नियम

एयर इंडिया के यात्री प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास में 7 किलोग्राम तक वजन वाला हैंड बैग ले जा सकते हैं। इसका डायमेंशन 115 सेंटीमीटर (लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई) अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स 10 किलोग्राम तक का बैग ले जा सकते हैं। प्रत्येक यात्री केबिन बैगेज के अलावा लैपटॉप बैग या लेडीज पर्स भी ले जा सकता है। बशर्ते वह सीट के नीचे समा सके और उसका वजन 3 किलोग्राम से अधिक न हो।

एयर इंडिया की हैंड बैग के लिए गाइडलाइंस

भारतीय सुरक्षा नियमों के अनुसार, प्रत्येक यात्री केवल एक हैंड बैगेज ले जा सकता है।

अगर बैगेज का वजन या आकार तय सीमा से अधिक हुआ, तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

2 मई 2024 से पहले जारी किए गए टिकटों के लिए पुराने नियम लागू होंगे।

विशेष बैगेज (जैसे संगीत उपकरण) के लिए अतिरिक्त सीट बुक की जा सकती है।

हालांकि, इसका वजन 75 किलोग्राम से अधिक न हो और वह सुरक्षित रूप से सीट पर बांधे जा सकें।

इंडिगो का हैंड बैग के लिए नियम

प्रत्येक यात्री को अधिकतम 7 किलोग्राम वजन और 115 सेंटीमीटर (लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई) तक का एक हैंडबैग ले जाने की अनुमति है। यात्री एक लेडीज पर्स या लैपटॉप बैग ले जा सकती हैं। लेकिन, इसका वजन 3 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई महिला यात्री लेडीज पर्स के साथ लैपटॉप बैग नहीं कैरी कर सकती। अगर कोई यात्री तय वजन से ज्यादा भारी लगेज ले जाता है, तो उससे अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है।

इंडिगो का चेक-इन बैगेज के लिए नियम

घरेलू उड़ान में एक यात्री 15 किलो तक का चेक-इन बैगेज ले जा सकता है।

डबल या मल्टीसीट बुकिंग में अतिरिक्त 10 किलो बैगेज की सुविधा मिलती है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक-इन बैगेज डेस्टिनेशन के आधार पर अलग-अलग है।

यह आमतौर पर 20 किलो से लेकर 30 किलो प्रति यात्री के हिसाब से तय है।

नियमों में क्यों बदलाव किया गया?

BCAS ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण हैंड बैग से जुड़े नियम बदले हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से हवाई यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2024 में फ्लाइट में सफर करने वाली संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे एयरपोर्ट पर भी बोझ बढ़ रहा है। नए नियमों से सिक्योरिटी चेक में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा।

पहले वजन की लिमिट कितनी थी?

नियम बदलने से पहले फ्लाइट में हैंड बैग ले जाने की सीमा अधिक थी। यह न्यूनतम 8 किलो से लेकर अधिकतम 12 किलो के बीच थी। हालांकि, नियमों में बदलाव के बाद यह लिमिट घटकर मिनिमम 7 से मैक्सिमम 10 किलो तक आ गई है। पहले इकोनॉमी में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलोग्राम और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलोग्राम की सीमा थी।

सफर के दौरान इन बातों का रखें ख्याल

एक यात्री अब सिर्फ एक हैंड बैग ले जा सकेगा। यह नियम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स के लिए होगा।

अगर आप एक से अधिक बैग ले जाएंगे, तो आपको अतिरिक्त बैग की जांच करवानी होगी।

इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी के यात्री अधिकतम 7 किलोग्राम तक वजन का एक हैंडबैग ले जा सकेंगे।

फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वाले यात्रियों के लिए वजन की लिमिट 10 किलोग्राम तक तय की गई है।

अगर 2 मई, 2024 से पहले फ्लाइट बुक की है, तो इकोनॉमी क्लास के यात्री 8 किलो तक हैंड बैग ले जा सकते हैं।

प्रीमियम इकोनॉमी यात्री 10 किलोग्राम और फर्स्ट क्लास -बिजनेस क्लास के यात्री 12 किलोग्राम का हैंड बैग ले जा सकते हैं।

नए नियम सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए लाए गये हैं।

अगर आपका हैंड बैग तय वजन और साइज के अंदर होगा, तो आप एयरपोर्ट पर देरी और असुविधा से बच जाएंगे।

सोने के सिक्कों से लेकर झाड़ू तक... स्विगी इंस्टामार्ट पर क्या-क्या खरीद रहे हैं लोग?

परिवहन विशेष न्यूज

अब बड़े शहरों में 10 से 30 मिनट में सिर्फ सब्जी-दूध ही नहीं कपड़े से लेकर मेकअप और यहां तक कि आईफोन भी डिलीवर हो रहे हैं। इतने कम समय में डिलीवरी कर देने से इसे क्विक कॉमर्स का नाम दिया गया है। क्विक कॉमर्स का कारोबार पिछले दो साल में तीन गुना बढ़ गया है। स्विगी इंस्टामार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारी से जुड़े दिलचस्प डेटा शेयर किए हैं।

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी स्विगी के साल 2024 काफी शानदार रहा। इस साल कंपनी का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा। साथ ही, वह अपना आईपीओ लाकर शेयर मार्केट में भी लिस्ट हुई। 2024 में स्विगी के क्विक कॉमर्स सेगमेंट स्विगी इंस्टामार्ट ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया। स्विगी ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का डेटा शेयर किया है, जिनसे कई दिलचस्प बातें पता चलती हैं।

ग्राहक किन चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं?

बड़ी खरीदारीः दिल्ली और देहरादून के यूजर्स ने स्विगी इंस्टामार्ट पर 20 लाख रुपये से अधिक खर्च किए। उन्होंने ज्यादातर आटा, दूध और तेल जैसे घरेलू सामान खरीदे।

पेट लवर्सः मुंबई के एक ग्राहक ने पालतू जानवरों के लिए खरीदारी पर 15 लाख खर्च रुपये खर्च कर दिए। इसमें खासकर कुत्ते और बिल्ली का खाना शामिल था।

गैजेट प्रेमीः चेन्नई के एक कस्टमर ने 1.25 लाख रुपये खर्च कर 85 इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण खरीदे।

आम का दीवानगीः हैदराबाद में एक ग्राहक ने मई में 35,000 रुपये सिर्फ आम खरीदने पर खर्च कर दिए।

किस समय पर क्या खरीद रहे थे ग्राहक?

सुबह (4-7 बजे): दूध, सब्जियां, और अंडे सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए।

रात (10 PM - 4 AM): चिप्स, आइसक्रीम, और कोल्ड ड्रिंक्स रात के समय की सबसे पसंदीदा चीजें रहीं।

शाम (8-9 बजे): सैनिटरी पैड्स के लिए सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए। नवंबर में दर्द निवारक उत्पादों की मांग सबसे अधिक रही।

ग्राहकों ने त्योहारों पर क्या खरीदा?

धनतेरसः अहमदाबाद के एक स्विगी इंस्टामार्ट कस्टमर ने सोने के सिक्कों पर 8,32,032 रुपये खर्च किए।

दीवालीः पूरे भारत में झाड़ू पर 45 लाख रुपये खर्च किए गए। दिल्ली ने पोकर चिप्स पर 4.6 लाख खर्च कर दिए।

रक्षाबंधनः 8 लाख राखियां डिलीवर की गईं। इसमें मुंबई के एक कस्टमर ने अकेले 31 राखियां ऑर्डर कीं।

वेलेंटाइन डेः हर मिनट 307 गुलाब के ऑर्डर किए गए।

'हम खतरनाक युग में जी रहे हैं', विशेषज्ञों ने चेताया; 2024 रहा अब तक का सबसे गर्म साल

साल 2024 अब के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल रहा है। इस साल औसतन 41 दिन अधिक भीषण गर्मी पड़ी है। धरती के मौसम को लेकर जारी एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बढ़ती गर्मी की वजह जलवायु परिवर्तन बताई गई है जिससे धरती का औसतन तापमान भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने इसे लेकर चेताया है।

जलवायु वैज्ञानिकों के दो समूहों - वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) और क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा जारी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2024 में औसतन 41 दिन और खतरनाक गर्मी पड़ी। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा, जहां लोगों को 130 से अधिक अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना करना पड़ा।

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। एक नई रिपोर्ट में भी इस ओर संकेत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में 2024 में औसतन 41 दिन और भीषण गर्मी पड़ी।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के हवाले से बताया कि 2024 अब तक के सबसे गर्म साल के रूप में समाप्त होने वाला है और यह पहला वर्ष होगा, जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा।

छोटे द्वीपीय देशों पर प्रभाव अधिक

जलवायु वैज्ञानिकों के दो समूहों - वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) और क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा जारी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2024 में औसतन 41 दिन और खतरनाक गर्मी पड़ी। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा, जहां लोगों को 130 से अधिक अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना करना पड़ा।

वैज्ञानिकों ने 2024 में 219 चरम मौसम की घटनाओं की पहचान की और उनमें से 29 का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 26 चरम मौसम की घटनाओं में कम से कम 3,700 लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र चरम मौसम की घटनाओं में मारे गए लोगों की कुल संख्या सैकड़ों हजारों में होने की संभावना है।'

बाढ़ का बढ़ता खतरा

रिपोर्ट से पता चला है कि सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में बाढ़ की सबसे घातक घटना थी, जिसमें कम से कम 2,000 लोग मारे गए थे। अध्ययन में पाया गया कि यदि ग्लोबल वार्मिंग दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जो 2040 या 2050 के दशक की शुरुआत में हो सकती है, तो इन क्षेत्रों को हर साल इसी तरह की भारी वर्षा की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

WWA के प्रमुख और इंपीरियल कॉलेज, लंदन में जलवायु विज्ञान के वरिष्ठ व्याख्याता फ्रेडरिक ओटो ने कहा, 'फॉसिल फ्यूल वार्मिंग के प्रभाव 2024 की तुलना में कभी भी स्पष्ट या अधिक विनाशकारी नहीं रहे हैं। हम एक खतरनाक नए युग में रह रहे हैं।'

'जीवाश्म ईंधन से दूर होना चाहिए'

उन्होंने कहा, 'हम अच्छी तरह जानते हैं कि हालात को और खराब होने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा - जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करना। 2025 के लिए शीर्ष संकल्प जीवाश्म ईंधन से दूर जाना होना चाहिए, जिससे दुनिया अधिक सुरक्षित और स्थिर स्थान बन जाएगी।'

साइलेंट प्रधानमंत्री के तमगे पर बोले थे मनमोहन सिंह- 'मैं डरता नहीं हूं...'

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में पड़ता है। उनके बेहद शांत और सरल स्वभाव के लिए हर कोई उनकी तारीफ करता था। लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें साइलेंट पीएम का तमगा दे दिया था। मनमोहन सिंह ने इसे लेकर 2018 में अपनी किताब के विमोचन के दौरान चुप्पी तोड़ी थी।

नई दिल्ली। दिल्ली एम्स में गुरुवार रात डॉ. मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वह 92 साल के थे। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। डॉ. सिंह को उनके बेहद शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था।

अपने सरल स्वभाव और ज्ञान के कारण डॉ. मनमोहन सिंह को राजनीतिक सीमाओं से परे भी सम्मान प्राप्त था। लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें 'साइलेंट पीएम' का तमगा दे दिया था। इस पर उन्होंने दिसंबर 2018 में जाकर चुप्पी तोड़ी थी और विरोधियों को जवाब दिया था।

विरोधियों को दिया था जवाब

डॉ. मनमोहन सिंह ने 2018 में 'चेंजिंग इंडिया' नाम से एक किताब लिखी थी। इसके विमोचन के दौरान उन्होंने कहा था, 'लोग कहते हैं कि मैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हूं। मुझे लगता है कि ये किताब खुद ही बोलेगी। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैं वह प्रधानमंत्री नहीं हूं, जो प्रेस से बात करने में डरता है।'

मैं प्रेस से निरंतर मिलता हूं। जो भी विदेश यात्रा मैंने की है, मैंने प्लेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या लैंडिंग के तुरंत बाद किया है। इस किताब में मेरे उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र किया गया है।

- डॉ. मनमोहन सिंह

डॉ. मनमोहन सिंह 2004 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह एक महान अर्थशास्त्री थे। कई राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक समस्याओं के समय भी उन्होंने देश के हित में फैसले लिए। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला।

मनमोहन सिंह ने लिखी थी किताब

उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री भारत में दो कार्यकाल पूरा किया। ऐसा करने वाले वह जवाहर लाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल में मनरेगा और शिक्षा का अधिकार और न्यूक्लियर डील जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। 1991 में देश के वित्त मंत्री के रूप में डॉ. सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था से लाइसेंस राज खत्म कर दिया।

पंजाब प्रांत में हुआ जन्म

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में पड़ता है। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की।

इसके बाद कैम्ब्रिज गए और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एलान कर दिया कि वह राजनीतिक सफर से संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन नतीजों में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देश को आगे बढ़ाया....।

'कठिन से कठिन समय में वह देश को चलाने आगे बढ़े

टूटे नहीं वह कभी वह मौन साधक बन भारत के लिए लड़े

वह सरदार भारत की ढाल बन कर असरदार बना

भारत के डॉ मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाया।

रुपये की ढापली को व्यवस्था के अर्थ के साथ जोड़ा

अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ कर उसे गिरने से बचाया

अर्थशास्त्री ऐसे की सदियों तक याद रहेंगे

भारत के डॉ मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाया।

हर पल हर समय अपने आप को राष्ट्र की भलाई के लिए लगाया

प्रोफेसर से प्रधानमंत्री तक उस आम व खास ने देश का भाल बढ़ाया

भारत माता के उसी सच्चे सपूत ने देश का गौरव बढ़ाया

सदा जीवन उच्च विचार नहीं घमंड रखा उन्होंने देश को आगे बढ़ाया।

हम सभी ने देखा लोकतंत्र के प्रहरी मनमोहन सिंह का जादू

आखिरी दम तक अपना फ़र्ज़ निभाया

नहीं भूलेगा देश उन्हें जिन्होने देश का मान बढ़ाया

भारत को अंधेरे से उजलों की तरफ हमेशा आगे बढ़ाया।।

जब पाकिस्तान से आए अपने बचपन के दोस्त से मिले मनमोहन

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक किस्सा वर्ष 2008 का है जब उनकी मुलाकात उनके बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली से हुई जो पाकिस्तान से आए थे।

नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एम्स में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम के निधन के बाद उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक किस्सा 2008 का है, जब उनकी मुलाकात उनके बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली से हुई, जो पाकिस्तान से आए थे।

अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था जन्म

बता दें कि मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब क्षेत्र के एक गांव गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 में जब विभाजन हुआ तो उनका परिवार अपने पैतृक घर और रिश्तेदारों को छोड़कर भारत आ गया।

2004 में दोस्त को मनमोहन का लगा पता

दरअसल, वर्ष 2004 में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो यह खबर पाकिस्तान में उनके गांव तक पहुंची, जिससे उनके पुराने दोस्त राजा मोहम्मद अली को उनसे मिलने की इच्छा हुई। विभाजन के पहले दोनों जिगरी दोस्त थे। राजा अली अपने दोस्त मनमोहन सिंह को बचपन के उपनाम 'मोहना' से बुलाते थे। वे एक ही प्राथमिक विद्यालय में साथ-साथ पढ़ते थे।

2008 में मिले दोनों दोस्त

इसके बाद मई 2008 में राजा अली अपने दोस्त मनमोहन सिंह मिलने दिल्ली पहुंचे। दोनों 70 वर्ष के हो चुके थे। दोनों जैसे ही मिले उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को तोहफे दिए। अली अपने दोस्त मनमोहन सिंह के लिए गाह से मिट्टी और पानी लाए, साथ ही गांव की एक तस्वीर भी दी।

उन्होंने डॉ. सिंह को 100 साल पुराना शॉल और उनकी पत्नी गुरशरण कौर को दो कढ़ाईदार सलवार कमीज सूट भी भेंट की। बदले में पूर्व पीएम ने ने अली को एक पगड़ी, एक शॉल और एक टाइटन घड़ी का सेट भेंट किया। उस मुलाकात के दो साल बाद, 2010 में अली का 78 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के चकवाल जिले में निधन हो गया। सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए।

पूर्ब राज्यपाल रघुबर दास की सच्चाई तो जैसे-तैसे सामने आई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: ओडिशा के राज्यपाल पद से बर्खास्त किए गए रघुवर दास का 13 महीने का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। पदभार ग्रहण करने के दिन से ही वे विवादों में रहे। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जिस हद तक अपनी गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, वैसा ओडिशा के किसी भी राज्यपाल के मामले में पहले कभी नहीं देखा गया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आज पुरी गए रघुवर के बयान ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया कि उनका मुख्य लक्ष्य नवीन सरकार के खिलाफ माहौल बनाना था। पुरी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नवीन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवीन सरकार राज्य की जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। वे अपनी समस्याओं के प्रति उदासीन थे। इसको लेकर लोगों में गुस्सा था और यह चुनाव में भी दिखाई दिया। लोगों ने नवीन सरकार को हटाकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। उन्होंने सरकार बदलने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। कोई भी गवर्नर कभी भी मीडिया के समक्ष इस टिप्पणी में प्रयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसी भाषा का प्रयोग केवल पार्टी कार्यकर्ता और नेता ही करते हैं। ऐसा बयान देते हुए

रघुवर ने स्वीकार किया कि उन्होंने राजभवन को पार्टी कार्यालय में तब्दील कर दिया है। उनके बयान से स्पष्ट है कि ओडिशा चुनाव से पहले उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह सत्य थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह राज्यपाल के तौर पर अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे थे या फिर राजभवन से नवीन सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे? क्या नवीन सरकार को हटाने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य की जनता को धन्यवाद देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया ने संविधान के साथ विश्वासघात किया है।वह न केवल दलीय राजनीति में लिप्त रहे, बल्कि उन्होंने सरकारी मामलों में हस्तक्षेप करने और अपनी मर्जी से शासन चलाने का भी प्रयास किया। ओड़िया एकता को मुद्दा बनाने वाली राज्य की भाजपा सरकार रघुवर के बेटे की हरकतों से गहरे संकट में है। एक राज्य सरकारी कर्मचारी की उसके बेटे ने पिटाई कर दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन राज्य पुलिस प्रशासन राज्यपाल के बेटे पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं हो सका। क्योंकि राज्यपाल के रूप में रघुबीर ने उन पर कार्रवाई न करने का दबाव डाला था। उनके कारण मोहन माझी सरकार असहाय हो गई। नवीन सरकार के खिलाफ साजिश रचने के साथ ही रघुवर ने ओडिशा अस्मिता को भी ठेस पहुंचाने में संकोच नहीं किया।

गौरतलब है कि भाजपा नेता रघुबीर दास २014 से २019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। वह राज्य के पहले गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री थे। लेकिन २019 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बुरी तरह हार गई। इसके लिए उन्हें झारखंड की राजनीति से हटाकर ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ओडिशा राजभवन में रहते हुए वे झारखंड की राजनीति में भी सक्रिय रहे। हाल ही में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका से भाजपा आलाकमान भी नाखुश था। ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल के पद से उन्हें हटाए जाने का एक कारण यह भी था।

चोर से बरामद 25 लाख का सोना बेंचने में कानपुर के पूर्व थानाध्यक्ष समेत चार दोषी

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां एक साथी कर से बरामद किए गए 25 लाख के सोने को बेचने के मामले में पु पूरी की गई जांच में रेल बाजार के पूर्व थानाध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा समेत चार लोग दोषी पाए गए हैं ,जिनके खिलाफ अब पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की ओर से कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच कमेटी ने पूर्व एसओ विजय दर्शन शर्मा, अंडर ट्रेनिंग दरोगा रविंद्र श्रीवास्तव, एचसीपी आमिल हाफिज और कार चालक आकाश को दोषी माना है। जबकि हेड कांस्टेबल सुभाष तिवारी को क्लीन चिट दे दी है। आरोप है कि चारों दोषी पुलिस कर्मी सर्राफ की दुकान पर गए थे। जहां से सोना गलाकर चोर को छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने रेलबाजार एसओ रहे विजय दर्शन शर्मा समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित करके जांच के आदेश दिए गए थे। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने पर दरोगा विजय दर्शन बहाल हो गए थे, जबकि अन्य पुलिस कर्मी अभी भी निलंबित चल रहे है। इस बहुचर्चित मामले की जांच एडीसीपी ईस्ट राजेश श्रीवास्तव ने की थी। जिसमें उन्होंने थाना अध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा सहित और अंडर ट्रेनिंग दरोगा सहित चार लोगों को दोषी पाया है। अवगत कराते चलें कि बर्रा-6 में रहने वाली शिक्षिका शालिनी दुबे के घर से 10 अक्टूबर को 30 लाख से ज्यादा की चोरी हुई थी। तत्कालीन रेलबाजार एसओ विजय दर्शन ने चोरों को अरेस्ट करके 25 लाख का सोना बरामद किया और हड़प लिया था। इसके बाद चोरों को भी छोड़ दिया था, लेकिन बर्रा पुलिस ने चोरों को अरेस्ट किया तब दरोगा विजय दर्शन शर्मा द्वारा किए गए सोना बेचने के खेल का खुलासा हो गया था।

झारखंड एस सी बी ने नेतरहाट स्कूल अधिकारी को धर दबोचा,पचास हजार रिश्वत के साथ विधालय अधिकारी गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची। झारखंड की नामी गिरामी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एस सी बी टीम ने उसके प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बख्शी को ₹50,000/- घूस लेते हुए रंगे आज पकड़ा है ।विभागीय एस पी ने बताया कि विद्यालय में दुध की सप्लाई की करने वाला शिकायतकर्ता से आरोपी लगातार पैसे का मांग कर रहा था ।जिसको लेकर ऐस सी बी ने अपना रणनीति तैयार कर जाल बिछाया । एस सी बी ने शिकायतकर्ता को पैसे देकर रोशन कुमार के पास भेजा ।जैसे ही रोशन ने उसे अपना घर बुलाया वही तैयार एस सी बी ने रोशन को धर दबोचा ।एस सी बी एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि किसी रिश्वत खोर को बक्सा नहीं जायेगा ।

मन के तार और अल्फाज़

छेड़ा ना करो मन के तारों को झनझना जाते हैं,
देखो बैठे-बैठे ही सारे अल्फाज़ निकल आते हैं।
मैंने तुम्हें कभी जिनसे मिलवाया था,
क्या? अब भी तुम्हें सब याद आते हैं!
मेरे घर के सामने से वो गुजर जाते हैं।

छेड़ा ना करो मन के तारों को झनझना जाते हैं,
देखो बैठे-बैठे ही सारे अल्फाज़ निकल आते हैं।
अब तो हो ही जाती है सुबह से शाम,
मुझे कोई मेरा हाल भी नहीं है पूछता!
हाँ, निकल जाते हैं सब करते राम-राम।

छेड़ा ना करो मन के तारों को झनझना जाते हैं,
देखो बैठे-बैठे ही सारे अल्फाज़ निकल आते हैं।
ज़ेहन में अब तो सिर्फ़ ख्वाब ही होते हैं,
अब वो नहीं जो कहीं आफताब होते हैं!
आँसू भी तो गंगा-जमुना के पास रोते हैं।

संजय एम. तराणेकर

डुमरी विधायक जयराम महतो समेत आठ पर मामला दर्ज

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

सरायकेला। झारखंड की असल समस्या मुलबासी यानी दुसरे शब्दों में खतियानी , उस आन्दोलन से राजनीति सफर तय विधानसभा पहुंचने वाले विधायक जयराम महतो ने विगत चुनाव में वोट का मोड़ को ही बदल डाला फिर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई ।आज उस युवा विधायक पर कोयलांचल एक मामला दायर हुआ है । डुमरी के विधायक जयराम पर चंद्रपुरा थाने में इस सी सी एल के सुरक्षा पदाधिकारी 58 वर्षीय सुरेश कुमार सिंह ने यह केस दर्ज कराया है। जब की जयराम झारखंडी लड़ाई का हवाला देते हुए चार थाने के पुलिस एवं सी आई एस एफ को अवैध कोयला कारोबार में शामिल कहकर सी सी एल क्वार्टर देने पर देर रात पुलिस से ऊंची वार्तालाप कर रहे थे, यद्यपि क्वाटर्स कंपनी के थे ।तब रात आधी हो चुकी थी ,जहां पुलिस असमंजस महसूस दिख रही थी । वहीं विधायक अपनी विधायकी जेब में रखने की बात कह कर ऊंची आवाज में अपने एवं कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी नहीं होने देने पर देर रात गाड़ी के ऊपर बैठकर बोल रहे थे । उन्होंने साफ लहजे में कहा क्वाटर हम तब छोड़ देंगे जब अन्य क्वार्टर्स में कब्जा जमाये रखने वालों को खाली करेंगे ।

घटना की एक एफ आई आर में विधायक जयराम महतो और उनके आठ कार्यकर्ताओं पर रंगदारी पूर्वक अवैध रूप से कब्जा करने, सरकारी काम में बाधा डालने तथा क्वार्टर में रखे गए सामान की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। सुरेश कुमार सिंह ने एफआईआर में बताया है कि 25 दिसंबर की शाम लगभग 5:30 बजे उनको यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मकोली स्थित क्वार्टर में कुछ अज्ञात लोग जाकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और उन मकानों में जो लोग पूर्व से रह रहे हैं उन प्रशिक्षु पदाधिकारी का सामान हटा रहे हैं और बाहर में काफी भीड़ भाड़ लगाकर हल्ला कर रहे हैं ।इन पदाधिकारी को उन मकानों से भगा रहे हैं। आवेदन में बताया गया है कि उसकी सूचन सीसीएल के कई पदाधिकारी को आवेदक ने दी थी । जिस पर वे सभी सुरक्षाकर्मी गए तो देखा कि 25 से 30 अज्ञात लड़का क्वार्टर के अंदर घुसे हुए है और हल्ला गुल्ला कर रहे है। इसकी जानकारी भी सीसीएल प्रबंधन को भी दी ।

घटना की नजाकत को देखते हुए चंद्रपुरा , नवाडी, गांधी नगर बोकारो पुलिस भी वहां पहुंची । विधायक जयराम ने मौके पर कहा हमें गोली मार दो , जालियांवाला बना दो इतनी पुलिस क्यों ? जयराम समेत आठ नामजद युवकों , तीस चालीस के करीब अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का अनुरोध पर मामला दर्ज हुआ है । देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में इस युवा विधायक ने जिस प्रकार अपनी व्यक्तव्य को रखा था उससे आंख मूंद दूध -मलाई खा रहे अनेको को उनकी बात रास नहीं आयी थी । वैसे भी कोयलांचल हो या लौहांचल झारखंड में ये जगह अवैध कमाई का बड़ा अड्डा रहा है । मामला क्या है, माजरा क्या है हकीकत आने वाला समय ही बहुत कुछ बताएगा अगर मामला विधानसभा जयराम मुखर हुए तब । अनेकों ने इस दिन की प्रतिक्षा में होने की बात कही है ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023